BRLF

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

BRLF
BHARAT RURAL
LIVELIHOODS FOUNDATION

सरकारों के साथ साझेदारी में सिविल सोसाईटी के कार्यों को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था

वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्षः 2024–25

विषय-सूची

अध्यक्ष का संदेश 7

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश 8

भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ): परिचय 9

बीआरएलएफ आउटरीच 12

बीआरएलएफ का गुणक प्रभावः (उत्तोलन) संसाधनों का अधिकतम उपयोग 14

बीआरएलएफ राज्य भागीदारी परियोजनाएँ 15

- कृषि उत्पादन क्लस्टर कार्यक्रम, ओडिशा (चरण 2) 15
- डीडब्ल्यूआईएमयू (DWIMU) परियोजना, बीटीआर असम 16
- उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़ (चरण 2) 17
- जीवि दाः हासा उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, झारखंड 18
- उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, महाराष्ट्र 19

सीएसआर परियोजनाएँ और विशेष पहल 20

- उत्कल्स एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन (UANAT) उत्कल कृषि परिवर्तन कार्यान्वयन परियोजना 20
- एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना 21
- डी–नोटिफाइड ट्राइब्स (DNT) परियोजना 22

2024–25 में नई परियोजनाएँ 23

- ग्रीन कॉलेज ओडिशाः आदिवासी महिला किसानों के लिए ग्रीन वैल्यू वेब का निर्माण 23
- सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) तक पहुंच सुरक्षित करना 24
- कृषि पारिस्थितिकी–आधारित क्षेत्रीय मॉडल लैंडस्केप परिवर्तन (AgRMLT) 25

बीआरएलएफ विजन कार्यान्वयन 27

आर्थिक अनूकलनता का सृजन – निचले स्तर को सुरक्षित करना 28

- सिंचाई और आजीविका संपत्ति निर्माण 29
- एकीकृत और विविध कृषि प्रणालियाँ 31
- पशुधन और मुर्गी पालन आधारित आजीविका 34
- सामूहिक कृषि, उत्पादक समूह और ग्रामीण उद्यम 36

जलवायु–संवेदी/उत्तरदायी ग्रामीण विकास – अनुकूलन संवर्धन और संतुलन की पुनर्स्थापना 39

- वाटरशेड और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) 40
- वृक्षारोपण, कृषि वानिकी और पुनर्वनीकरण 42
- जलवायु– अनूकूल कृषि 44

सिस्टम, संस्थाएँ और साझेदारी – स्थायी परिवर्तन के लिए मजबूत आधार 47

- सरकारी योजनाओं का तालमेल और संस्थागत भागीदारी 48
- स्थानीय शासन, सीएसओ और क्षमताओं को मजबूत करना 49
- लर्निंग, साक्ष्य और नवाचार के लिए व्यवस्थाएँ 52

महिलाओं और सीमान्त समुदायों का सशक्तीकरण – बाधाएँ हटाओ और क्षमता बढ़ाओ 55

महिलाओं के नेतृत्व वाली आजीविका और आर्थिक उद्यम 55

सामुदायिक संस्थानों में सहभागिता 57

अधिकार, मान्यता और अधिकार/हकदारी सुरक्षित करना 59

समन्वय 2025: विभिन्न स्वरों और विचारों का संगम 61

पैनल चर्चा – विचार साझा करना, प्रेरक कार्रवाई 63

क्षमता निर्माण 65

शैक्षणिक संस्थानों के साथ बीआरएलएफ साझेदारियाँ 65

ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फैलोशिप प्रोग्राम 67

वाटरशेड प्रबंधन पर डिजिटाइज्ड मॉड्यूल 67

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन 69

चार राज्यों में बीआरएलएफ कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन 69

विश्लेषणात्मक केस स्टडीज निर्माण 70

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में DWIMU परियोजना के लिए बेसलाइन 71

ग्रीन कॉलेज ओडिशा के लिए बेसलाइन की शुरुआत 72

राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) का "गरीबी उपशमन और आजीविका पर अध्याय" 72

निगरानी, मूल्यांकन और सीख (मोनिटरिंग, इवेल्यूएशन व लर्निंग) 74

एक समग्र एमईएल फ्रेमवर्क 74

अत्याधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआईएस (MIS) 74

एक एमआईएस, एक डेटाबेस 75

बीआरएलएफ में राजभाषा प्रोत्साहन पहल 76

रणनीतिक साझेदारी और संसाधन संग्रहण 2024 – 2025 77

भागीदारियाँ 80

शासन व्यवस्था: पारदर्शिता और जवाबदेही, ऑडिट और संगठनात्मक संरचना 83

वित्तीय प्रणाली, नियंत्रण, ऑडिट और काम पर पारदर्शिता 83

अनुदान प्रबंधन, एमआईएस और मानव संसाधन एवं एडमिन के लिए ऑनलाइन ऐप 83

ऑडिट 83

संगठनात्मक संरचना 83

वित्त और लेखा 85

ऑडिट किए गए खाते 2024–25 87

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय मित्रों,

मैं अपार गर्व और उत्साह के साथ वर्ष 2024–25 की भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीते वर्ष के दौरान, बीआरएलएफ ने सरकार, नागरिक समाज एवं समुदायों के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया है, जिसके फलस्वरूप देश के कुछ सबसे वंचित जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी और सतत आजीविका को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

इस वर्ष हमारे कार्यक्रमों ने अपना दायरा और प्रभाव दोनों को विस्तृत एवं गहरा किया है। राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों सीएसओ और परोपकारी साझेदारों के साथ रणनीतिक सहयोग ने हमें प्रयासों का विस्तार करने और उन्हें समुदायों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने में मदद की है। इसके परिण ामस्वरूप कृषि उत्पादकता, उत्पादक समूहों की मजबूती, महिलाओं के सशक्त नेतृत्व और जलवायु–संवेदी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साथ ही, हमारे ज्ञान प्रबंधन और क्षमता–विकास ने स्थानीय नेतृत्व को सशक्त किया है और राष्ट्रीय स्तर पर नीति–निर्माण को सकारात्मक दिशा दी है।

हमारी कार्यप्रणाली का एक प्रमुख आधार राज्य साझेदारी मॉडल है, जो संसाधनों को जोड़ने, कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाने और समुदायों के साथ विश्वास बनाने में सहायता करता है। इस वर्ष प्राप्त हुई प्रत्येक उपलब्धि हमारे साझेदारों, टीम के सदस्यों और समुदायों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास एवं साझा दृष्टिकोण का परिणाम है।

भविष्य में भी बीआरएलएफ का यही संकल्प है कि वह इसी तरह अपना प्रभाव बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और जमीनी अनुभव को संस्थागत क्षमता से जोड़ने पर काम करता रहेगा। हम अपने सहयोगी संगठनों, दानदाताओं, सरकारों और सबसे बढ़कर उन समुदायों के आभारी हैं, जो हमारी प्रेरणा हैं और हमें कार्य करने का उद्देश्य प्रदान करते हैं। साथ ही, मैं हमारे निदेशक मंडलध्बोर्ड और टीम के सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण इस यात्रा को सफल बनाने में मजबूत नींव प्रदान करती हैं।

आइए, हम मिलकर एक आत्मनिर्भर, न्यायसंगत और सतत ग्रामीण एवं जनजातीय भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें।

श्री गिरीश प्रभुणे
अध्यक्ष,
भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय साथियों,

मैं आपको सहर्ष अवगत करवाना चाहता हूँ कि पिछला वर्ष हमारे लिए सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ सीखने, बढ़ने और नवाचारों से भरा रहा है। बीआरएलएफ ने ग्रामीण विकास की चुनौतियों के बीच न सिर्फ अपने कदम मजबूत किए, बल्कि साझेदारियों को भी और गहराई दी। हमने कोशिश की कि हर काम में समुदाय हमारे साथ बराबरी से जुड़ें और हमारी प्रणालियाँ और अधिक प्रभावी व सतत बनें।

राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और दानदाता भागीदारों के साथ मिलकर हम पाँच राज्यों में लगभग 3.50 लाख परिवारों तक पहुँचे। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, मजबूत संस्थाएँ, अधिकारों तक आसान पहुँच और निर्णय लेने में इनकी सक्रिय भागीदारी इत्यादि के माध्यम से इन परिवारों की जिंदगी में बदलाव देखना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे काम की असली ताकत रही है प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग और जलवायु अनुकूल पद्धतियाँ, जो भविष्य को सुरक्षित बनाती हैं।

पिछले वर्ष हमने 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया–चाहे वे समुदाय के सदस्य हों या ग्रामीण इलाकों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ता। ये प्रशिक्षण केवल ज्ञान साझा करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोगों को अपने गाँव और अपने जीवन के लिए नए रास्ते खोजने की प्रेरणा भी देते हैं।

हमारे लिए गर्व की बात है कि "समन्वय 2025" जैसे आयोजन द्वारा हमने विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर साझेदारी और सहयोग की ताकत को उजागर करने हेतु एक व्यापक साझा मंच प्रदान किया। इन अवसरों ने जनजातीय समुदायों के समक्ष खड़ी संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित किया।

आने वाले समय में हम अपनी रणनीतियों को और निखारेंगे, सफल पहलों को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा हर प्रयास ग्रामीण और जनजातीय समुदायों का जीवन बेहतर बनाने में सफलता हासिल करे। इस सफर में मैं हमारे बोर्ड, टीम, साझेदारों, दानदाताओं और सबसे बढ़कर, उन समुदायों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनका विश्वास और धैर्य हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है।

हम सब मिलकर, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने का प्रयास करते रहेंगे, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने पर हमारा विशेष जोर रहेगा।

कुलदीप सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ)

भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ): परिचय

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (www.brlf.in) एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी अंचलों में, विकास कार्यों को गति प्रदान करना है।

बीआरएलएफ का अधिदेश कई प्रमुख कार्यों को सम्मिलित करता है–जैसे योजनाओं के प्रावधान और उनके वास्तविक परिणामों के बीच अंतर को कम करना, सरकारी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार करना, नागरिक समाज संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराना तथा समावेशी विकास के लिए साझेदारियों को प्रोत्साहित करना।

बीआरएलएफ की विशिष्ट राज्य साझेदारी संरचना सहयोगात्मक मॉडल' को आगे बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs), नागरिक समाज संगठनों (CSOs), समुदायों और दानदाता संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर कार्य करता है। इस मॉडल से सभी हितधारकों की परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी (monitoring) में भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे विकास कार्य अधिक प्रभावी और परिणामकारी बनते हैं।

यद्यपि बीआरएलएफ का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत है, परंतु इसका विशेष ध्यान मध्य भारत के उन दस राज्यों पर केंद्रित है जहाँ आदिवासी जनसंख्या अधिक है।

विजन

बीआरएलएफ एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां भारत में ग्रामीण और जनजाति समुदाय आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा, सर्वांगीण समृद्धि, सशक्तीकरण के साथ–साथ गरिमामय जीवन यापन करें।

मिशन

बीआरएलएफ का उद्देश्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में नागरिक समाज की कार्रवाई को विस्तृत कर कमजोर ग्रामीण समुदायों के जीवन और आजीविका को परिवर्तित करना है।

आधारभूत मूल्य

सहयोग:

बीआरएलएफ सहयोग और सामूहिक बुद्धि मत्ता की शक्ति में विश्वास करता है। हम ग्रामीण समुदायों में सार्थक और उचित प्रभाव और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नागरिक समाज संगठनों, सरकारों, समुदायों और निगमों के साथ उद्देश्यपूर्ण तालमेल व सार्थक साझेदारी की सक्रिय रूप से तलाश करते हैं। हम सहयोग की संस्कृति, साथ मिलकर सीखने, विविध विचारों का सम्मान करने, टीम भावना और खुली बातचीत को बढ़ावा देते हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही:

बीआरएलएफ अपने सभी कार्यों में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही बना, रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सुशासन के सिद्धांतों का पालन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संसाधनों, अधिकारों और शक्तियों का उपयोग व वितरण जिम्मेदारी से हो, ताकि सबको समान अवसर और परिणाम मिल सकें।

नवाचार:

बीआरएलएफ नवाचार को अपनाता है और ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए विचारों, दृष्टिकोणों और समाधानों की तलाश करता है। हम सतत विकास और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मकता, सीखने और नवीन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं।

उत्कृष्टता:

हम उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उच्चतम मानकों के लिए प्रयास करते हैं। हम प्रभावशाली और सतत परिणाम देने का प्रयास करते हैं, जमीनी स्तर पर सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लगातार परिष्कृत करते हैं।

बीआरएलएफ का अधिदेश

- सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करके कार्यक्रम के वित्तपोषण और वास्तविक प्रभावों के बीच की खाई को पाटना।
- मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्र में समावेशी विकास की दिशा में राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), पंचायती राज संस्थानों और व्यवसायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता/कार्य कुशलता का निर्माण करना।
- समुदाय–आधारित सतत प्रथाओं को उन्नत करना।
- परियोजना प्रबंधन और संस्थागत लागतों के लिए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को अनुदान सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विषयगत कार्यक्षेत्र

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:
मृदा, भूमि और जल संसाधन संवर्धन

सतत कृषि और संबद्ध पहलों को बढ़ावा देना:
कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना

महिलाओं के नेतृत्व वाले सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करना:
निर्माता समूह, कंपनियां, समूह

बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी सक्षम क्षमता निर्माण:
सीएसओ, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, इकोप्रेन्योर और सामुदायिक संस्थान

अधिकार और पात्रता
प्रधानमंत्री की प्रमुख योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

बीआरएलएफ प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण

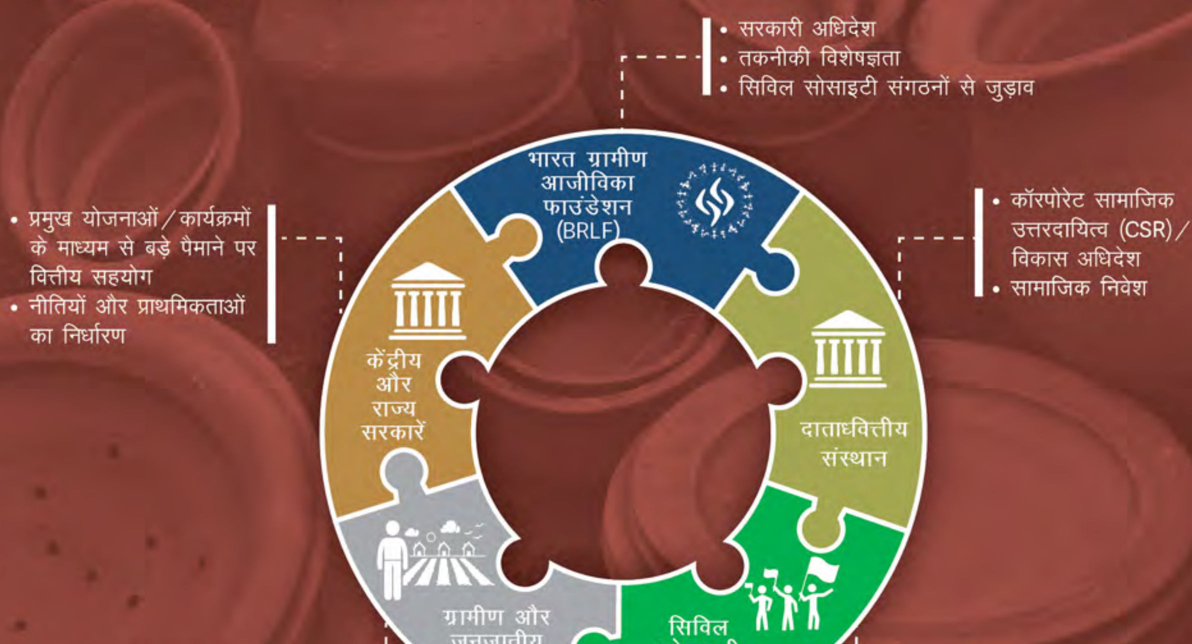

बीआरएलएफ छोटे लेकिन प्रभावशाली सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) को राज्य सरकारों और दाताओं से जोड़ता है, जिससे रणनीतिक वित्तपोषण और सहयोग के साथ बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संभव हो पाता है।

बीआरएलएफ आउटरीच (पहुँच)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25	2014–15 से संचयी/कुल
कुल राज्य	5 असम (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र), छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा	11 असम (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र), छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलांगना
कुल जिले	40	117
कुल ब्लॉक	120	385
कुल ग्राम पंचायतें	3,219	5,234
कुल गाँव	7,054	24,618
कुल परिवारः (कम से कम एक पहल से हुए लाभान्वित)	3,49,375	13,71,466
कुल अनुसूचित जनजाति परिवार	2,59,952	9,07,210
कुल लाभान्वित महिला किसान	1,50,542	8,07,588
कुल लाभान्वित छोटे और सीमांत किसान	3,36,419	6,67,212

बीआरएलएफ का गुणक प्रभाव: संसाधनों का उपयोग

बीआरएलएफ "संसाधनों के उपयोग (Leverage)" को इस रूप में परिभाषित करता है कि उपलब्ध धन, संसाधनों और क्षमताओं का रणनीतिक प्रयोग कर सरकारी कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ और प्रभाव प्राप्त किया जाए। इसका आशय है कि सरकारी योजनाओं और अधिकारों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि व्यक्तिगत प्रयासों से संभव परिणामों से कहीं अधिक बड़े और ठोस नतीजे मिल सकें।

राज्य साझेदारी परियोजनाओं के अंतर्गत बीआरएलएफ ग्रामीण विकास और आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विशाल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। बीआरएलएफ की सभी परियोजनाओं का एक प्रमुख हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकारों के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से संसाधनों का समन्वय हो और साथ ही संबंधित राज्यों में सिविल सोसाइटी की गतिविधियों का भी विस्तार हो। बीआरएलएफ सरकारी वित्तीय सहयोग को निजी क्षेत्र के निवेश और अन्य संसाधनों के साथ मिलाकर बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत सिद्ध पहलों का बड़े स्तर पर विस्तार, अधिक परिवारों तक पहुँचना, नए संसाधन और परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका की उत्पादकता और विविधता को बढ़ाना तथा लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार करना शामिल है।

इसकी स्थापना के बाद से कुल (करोड़ रुपये में)

बीआरएलएफ निवेश (सीएसओ को अनुदान) – **190.44**

सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ – **5,213.68**

सह–वित्त (सीएसआर और संस्थागत भागीदारी) – **356 करोड़ रुपये**

ग्रांट टू लीवरेज और को–फाइनेंस अनुपात – **1:29** (बीआरएलएफ द्वारा खर्च किए जाने वाले प्रत्येक रुपये के लिए, यह सरकार और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से 29 रुपये का लाभ उठाता है)

वित्तीय वर्ष 2024–25 (करोड़ रुपये में)

बीआरएलएफ निवेश (सीएसओ को अनुदान)	**20.44**
सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ	**526.68**
सह–वित्त (सीएसआर और संस्थागत भागीदारी)	**15.97**

राज्यवार उत्तोलन 2024–25 (करोड़ रुपये में)

1. बोडोलैंड, असम	**30.54**
2. छत्तीसगढ़	**116.7**
3. झारखंड	**217.8**
4. महाराष्ट्र	**46.14**
5. ओडिशा	**115.5**

बीआरएलएफ राज्य भागीदारी परियोजनाएँ

कृषि उत्पादन क्लस्टर कार्यक्रम, ओडिशा (चरण 2)

अवधिः	जूनवरी 2024 से दिसंबर 2028
जिलेः	12 जिले (बालांगीर, कालाहांडी, क्योंझर, ढेंकेनाल, मयूरभंज, कोरापुट, कंधमाल, रायगड़ा, नुआपाड़ा, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बौद्ध)
गाँवः	1,974
सरकारी भागीदारः	कृषि और बागवानी विभाग, ओडिशा आजीविका मिशन, मिशन शक्ति और अन्य संबंधित विभाग
द्वारा वित्त पोषितः	ओडिशा सरकार और बीआरएलएफ
सीएसओ भागीदारः	15

ओडिशा सरकार ने 6 नवम्बर 2018 को कृषि उत्पादन क्लस्टर (APC) पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य जनजातीय महिला किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। इस परियोजना को उद्यान एवं कृषि विभाग, ओडिशा लाइवलीहुड मिशन, मिशन शक्ति, बीआरएलएफ और अन्य संबंधित विभागों का सहयोग प्राप्त है। 14 सिविल सोसाइटी संगठनों और प्रदान (PRADAN) द्वारा, जो कि प्रमुख भागीदार है, इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता और आजीविका को बढ़ाने के लिए एपीसी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

पहले चरण की सफलता के बाद, 13 जून 2023 को आयोजित 7वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में APC 2.0 को मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के साथ परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2,000 अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने की योजना है, जो पहले से जुड़े 3,000 परिवारों के अतिरिक्त होंगे। एपीसी के पहले चरण में संस्थाओं को बनाना और मजबूत करना, बाजार से जुड़ाव बढ़ाना, जरूरी ढाँचे तैयार करना और आजीविका से जुड़ी संपत्तियाँ बनाना मुख्य उद्देश्य थे। जबकि एपीसी 2.0 का ध्यान नए परिवारों को जोड़ने, मूल्य शृंखला के विकास, आजीविका के अधिक अवसर बढ़ाने तथा समुदाय की बाजार तक पहुँच आसान बनाने पर है।

डीडब्ल्यूआईएमयू (DWIMU) परियोजना, बीटीआर असम

अवधिः	**जून 2022 से जून 2026**
जिलेः	**3 (बक्सा, तमुलपुर, उदलगुरी)**
ब्लॉक	**7**
गाँवः	**271**
सरकारी भागीदारः	**ग्रामीण विकास विभाग और अन्य संबद्ध लाइन विभाग, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, असम सरकार**
सीएसओ भागीदारः	**5**

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) परिषद के निमंत्रण पर लोगों के जीवन उत्थान के लिए एकीकृत प्रबंधन (डीडब्ल्यूआईएमयू) परियोजना के साथ विविधीकरण शुरू किया गया था। यह परियोजना एक संयुक्त कार्य बल द्वारा तीन दशकों के संघर्ष के कारण आजीविका और अन्य विकास कार्यक्रमों के मौजूदा कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान करने के बाद शुरू की गई थी। बीआरएलएफ और BTR सरकार के बीच जून 2022 में चार साल की अवधि (विस्तार योग्य) के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे DWIMU पहल का निर्माण हुआ।

इस परियोजना का उद्देश्य बोडोलैंड क्षेत्र में 40,000 अनुसूचित जनजाति और कमजोर परिवारों के जीवन और आजीविका में परिवर्तन लाना है। यह परियोजना प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने, आजीविका बढ़ाने और हथकरघा, रेशम उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़ (चरण 2)

अवधिः	**अक्टूबर 2024 से सितंबर 2028**
जिलेः	**12 (सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा)**
गाँवः	**2,597**
सरकारी भागीदारः	**छत्तीसगढ़ सरकार**
फंडिंग पार्टनर्स (वित्त पोषण सहयोगी):	**एक्सिस बैंक फाउंडेशन**
सीएसओ भागीदारः	**11**

बीआरएलएफ, एक्सिस बैंक फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ सरकार के मनरेगा आयुक्त ने मिलकर 2,50,000 छोटे और सीमांत परिवारों की आय को टिकाऊ रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से *हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना* की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य आधार प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) है, जिसके जरिए आजीविका के अवसरों में सुधार किया जा रहा है। मनरेगा और अन्य सरकारी संसाधनों का उपयोग करके इस परियोजना का लक्ष्य है – स्थायी सामुदायिक और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण करना, आजीविका के अवसरों को परतदार ढंग से विकसित करना, मिट्टी और जल संरक्षण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाना। इस प्रयास का अंतिम उद्देश्य है कि ग्रामीण समुदायों की आय और अनुकूलनता (resilience) बढ़े और दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित हो। पहले चरण (2018–2024) में चार प्रमुख रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया – जीआईएस मैपिंग के आधार पर जलग्रहण और पहाड़ी से घाटी तक की योजना, समुदाय–आध ारित क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों की क्षमता वृद्धि और संसाधनों से वंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता देना। एबीएफ और बीआरएलएफ द्वारा समर्थित सिविल सोसाइटी संगठन (CSOs) तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं और स्थानीय संस्थाओं की क्षमता मजबूत कर रहे हैं, जबकि राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ समय पर योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित कर रहा है।

इस सफलता के आधार पर दूसरे *चरण* (अक्टूबर 2024–सितंबर 2028) को मंजूरी दी गई है, जिसमें 13 जिलों के 35 ब्लॉक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य वाटरशेड विकास के जरिए सतत आजीविका सुधार को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाना है।

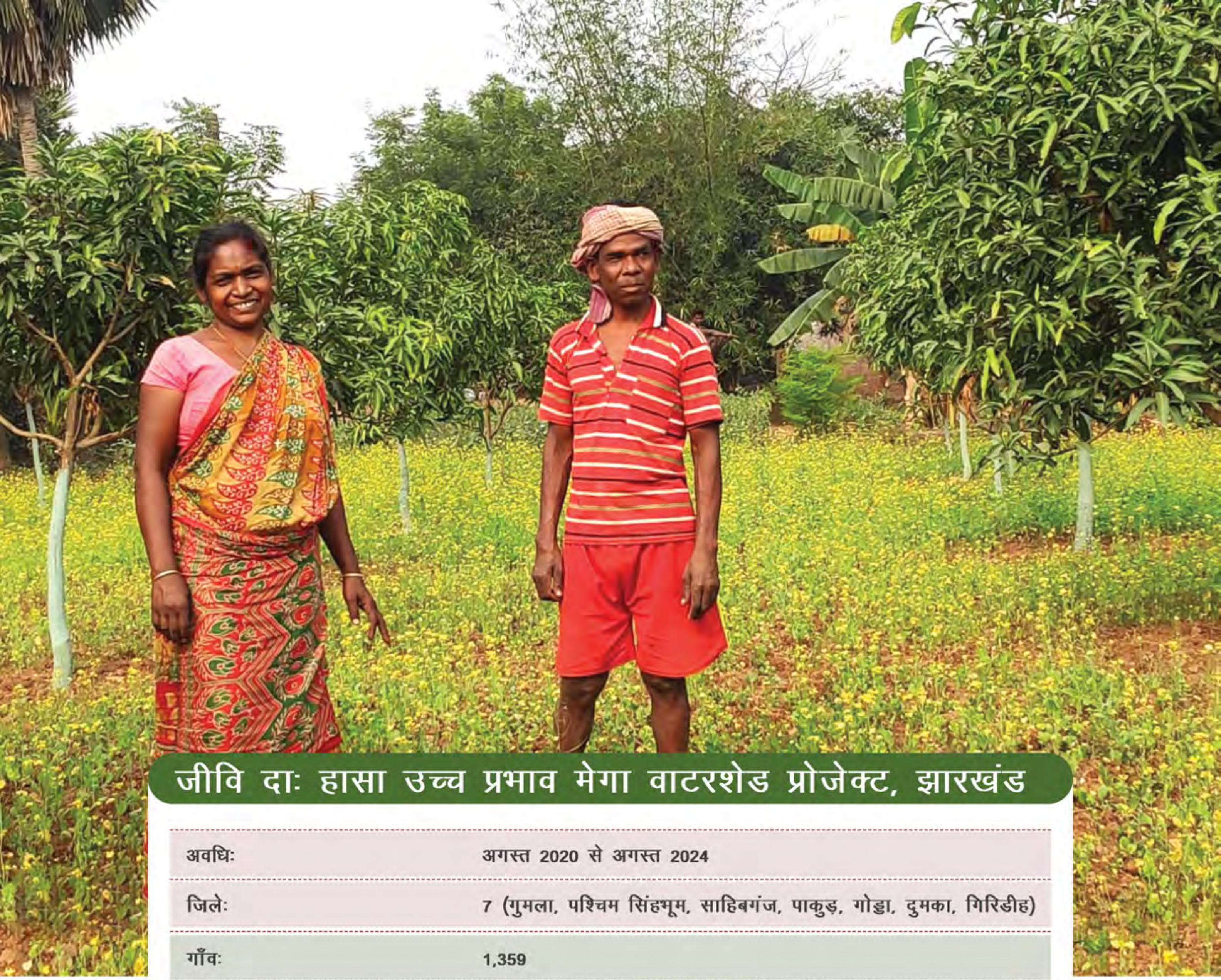

जीवि दाः हासा उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट, झारखंड

अवधिः	अगस्त 2020 से अगस्त 2024
जिलेः	7 (गुमला, पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह)
गाँवः	1,359
सरकारी भागीदारः	झारखंड सरकार
फंडिंग पार्टनर्सः	एसबीआई फाउंडेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और वेल्टहंगरहिल्फे (डब्ल्यूएचएच)
सीएसओ भागीदारः	11

झारखंड सरकार मनरेगा सेल और बीआरएलएफ के बीच इस संयुक्त पहल का उद्देश्य झारखंड के तीन प्रमुख क्षेत्रों के 24 ब्लॉकों में जनजातीय और कमजोर समुदायों के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण करना है। इस परियोजना में एकीकृत वाटरशेड दृष्टिकोण अपनाया जाता है, मनरेगा संसाधनों के माध्यम से भूमि और जल संरक्षण उपायों को लागू करता है और अन्य विभागों से अभिसरण समर्थन का लाभ उठता है।

बीआरएलएफ और सीएसओ तकनीकी विशेषज्ञता के साथ सरकारी संसाधनों को जोड़कर, साझेदारी व्यापक वाटरशेड विकास सुनिश्चित करती है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करते हुए ग्रामीण आजीविका को बढ़ाती है। यह सहयोगी मॉडल दर्शाता है कि कल्याणकारी योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में रणनीतिक गठबंधन कैसे प्रभाव को अधिकतम कर सकते हैं।

अब यह परियोजना 1 जून 2025 से 31 मार्च 2029 की समयसीमा के साथ अपने दूसरे चरण (जीवि दाः हासा 2.0) में प्रवेश कर गई है।

उच्च प्रभाव मेगा वाटरशेड परियोजना, महाराष्ट्र

अवधिः	जुलाई 2023 से जून 2028
जिलेः	5 (गढ़चिरौली, गोंदिया, नांदेड़, यवतमाल, चंद्रपुर)
गाँवः	731
सरकारी भागीदारः	महाराष्ट्र सरकार
फंडिंग पार्टनर्सः	एक्सिस बैंक फाउंडेशन
सीएसओ भागीदारः	10

यह परियोजना 'रिज–टू–वैली' यानी शिखर से घाटी तक के समग्र दृष्टिकोण को अपनाती है। इसका मतलब है कि पूरे वाटरशेड क्षेत्र की भूमि, जल और पारिस्थितिक संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल छोटे उद्यमों और व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र के सबसे वंचित जिलों में ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित हों और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। पांच वर्षों में, यह परियोजना जीआईएस के नेतृत्व वाली वैज्ञानिक योजना का उपयोग करके 4.39 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार करेगी, साथ ही साथ 4,000 ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को 400 उच्च क्षमता वाले उद्यमियों के लिए विशेष व्यवसाय सेटअप समर्थन के साथ इको–प्रेन्योर के रूप में प्रशिक्षित करेगी। यह परियोजना जलवायु–अनुकूल कृषि और ग्रामीण उद्यमिता को प्राथमिकता देती है। इस दोहरे फोकस का उद्देश्य अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों का उत्थान करना, सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए आय को बढ़ावा देना है।

सीएसआर परियोजनाएँ और विशेष पहल

उत्कल'स एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन (UANAT)/ उत्कल कृषि परिवर्तन कार्यान्वयन परियोजना

अवधिः	राज्यः	जिलेः	गाँवः	सरकारी भागीदारः	फंडिंग पार्टनर्सः	सीएसओ भागीदारः
नवंबर 2020 से अक्टूबर 2024	ओडिशा	2 (रायगढ़ा, कालाहांडी)	118	ओडिशा सरकार	उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल)	1

UANAT परियोजना का उद्देश्य तीन प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ाना हैरू आदिवासी क्षेत्रों में कृषि, जल संसाधन और पशुधन। इस परियोजना द्वारा भूजल पुनर्भरण में सुधार और खेती योग्य क्षेत्रों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे किसानों की आय, फसल पैटर्न और बाजार पहुंच में काफी सुधार होता है और अंततः ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित करके, इस परियोजना ने 600 एकड़ पहले अनुपयुक्त भूमि को खेती करने योग्य बनाया है। यह क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और सूखा प्रतिरोधी फसलों की शुरूआत से पूरित है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है और विविध कृषि पद्धतियाँ विकसित हुई हैं।

एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना

अवधिः	राज्यः	जिलेः	गाँवः	फंडिंग पार्टनर्सः
1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक	ओडिशा	रायगढ़	2	उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल)

इस परियोजना ने एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन द्वारा मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण द्वारा पानी की उपलब्धता और कृषि पद्धतियों में सुधार किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप मिट्टी की नमी बनाए रखने में सुधार हुआ, फसल की पैदावार में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि आय में वृद्धि हुई। इस परियोजना ने मूल्यवर्धन और बाजार लिंकेज के माध्यम से आजीविका में विविधता लाते हुए सतत कृषि, कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा दिया। दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय संस्थानों को मजबूत किया गया। इस परियोजना ने सफलतापूर्वक 160 वाटरशेड संरचनाएं बनाईं, जिससे क्षेत्र के कृषि परिदृश्य में सुधार हुआ।

डी–नोटिफाइड ट्राइब्स (DNT) परियोजना

अवधिः
1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक

जिलेः
महाराष्ट्र

जिलेः
अहमदनगर और पुणे

गाँवः
2

महाराष्ट्र में पारधी, कंजर, नट और सपेरा जैसे समुदायों सहित डी–अधिसूचित जनजातियों (डीएनटी) को ब्रिटिश शासन के दौरान "आपराधिक जनजातियों" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण ऐतिहासिक रूप से सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, जिससे इन समुदायों को आधिकारिक तौर पर गैर–अधिसूचित किया गया था। इसके बावजूद, डीएनटी समुदाय हाशिए और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निरंतर जूझते रहते हैं।

बीआरएलएफ ने अगस्त 2023 में डीएनटी/एनटी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया, जिसका उद्देश्य मुख्य समस्याओं को समझना और पारधी परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है। पद्मश्री गिरीश प्रभुणे के नेतृत्व में यह परियोजना महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे जिलों में पहले वर्ष में 150 से अधिक पारधी परिवारों, दूसरे वर्ष में 2,000 परिवारों और तीसरे वर्ष में 5,000 परिवारों की आजीविका की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है।

इस परियोजना का उद्देश्य आजीविका पहल, उद्यमिता को बढ़ावा देने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के माध्यम से पारधी समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, कृषि, बागवानी और पशुपालन सहित आय सृजन गतिविधियों के लिए 10.5 एकड़ भूमि का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना समुदाय और हितधारकों के साथ मिलकर सहयोग करती है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहभागी दृष्टिकोण का उपयोग करती है। पारधी परिवारों के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से क्षमता निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाती है।

2024–25 में शुरू की गई नई परियोजनाएँ

ग्रीन कॉलेज ओडिशाः आदिवासी महिला किसानों के लिए ग्रीन वैल्यू वेब का निर्माण

अवधिः
अक्टूबर 2024 से सितंबर 2028

सरकारी भागीदारः
ओडिशा सरकार

राज्यः
ओडिशा

सीएसओ भागीदारः
15

जिलेः
12 (कोरापुट, कंधमाल, रायगढ़ा, कालाहांडी, ढेंकनाल, क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बोलंगीर, बौध, नुआपाड़ा)

फंडिंग पार्टनर्सः
जर्मन सरकार और वेल्टहंगरहिल्फे का आर्थिक विकास सहयोग (बीएमजेड)

उत्कृष्टता के राज्य–स्तरीय केंद्र के रूप में परिकल्पित, ग्रीन कॉलेज ओडिशा का उद्देश्य सतत कृषि और पर्यावरण–उद्यम विकास में क्षमता निर्माण, नवाचार और तकनीकी सहायता के लिए तंत्रिका केंद्र बनना है। यह परियोजना जनजातीय समुदायों के बीच हरित आजीविका को बढ़ावा देने पर जोर देती है, जिसमें इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

ग्रीन कॉलेज कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ है, जो अब अपने दूसरे चरण (एपीसी 2.0) में है। ग्रीन कॉलेज ओडिशा चेंजमेकर्स को पोषित करने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे आदिवासी महिलाओं को कुशल उद्यमी, जलवायु–स्मार्ट किसान और पूरे ओडिशा में सतत ग्रामीण विकास के पथप्रदर्शक बनने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) तक पहुंच सुरक्षित करना

अवधिः
1 जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर 2027 तक

जिलेः
8 (जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिम मिदनापुर)

राज्यः
पश्चिम बंगाल

फंडिंग पार्टनर्सः
स्विस फिलांथ्रॉपी फाउंडेशन

इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक वन अधिकार क्लेम प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सरकार और नागरिक समाज के साथ जुड़ना है। यह बीआरएलएफ की संस्थागत क्षमता बढ़ाने, सीएसओ के साथ नेटवर्क बनाने और वन शासन से संबंधित नीतियों पर राज्य और राष्ट्रीय विभागों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह पहल स्वदेशी समुदायों को उनकी पारंपरिक जानकारी और क्षमता का उपयोग करते हुए वन संसाधनों का जिम्मेदार और स्थायी प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाती है जिससे लोग अपनी आजीविका की जरूरतों जैसे ईंधन, चारा, फल–फूल और अन्य वन उपज को सुरक्षित ढंग से प्राप्त कर सकें, साथ ही वनों की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे। इस प्रकार यह पहल स्थानीय लोगों की आर्थिक सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण – दोनों को साथ लेकर चलती है।

कृषि पारिस्थितिकी–आधारित क्षेत्रीय मॉडल लैंडस्केप परिवर्तन (AgRMLT)

अवधिः दिसंबर 2024 से नवंबर 2026 तक	**जिलेः** 1, छतरपुर	**फंडिंग पार्टनर्सः** जीआईजेड
राज्यः मध्य प्रदेश	**सरकारी भागीदारः** मध्य प्रदेश सरकार	**सीएसओ भागीदारः** 9

इस परियोजना का उद्देश्य मिलजुलकर और विभिन्न साझेदारों की भागीदारी से दो कृषि–पर्यावरण आधारित मॉडल क्षेत्र विकसित करना है। इसका फोकस ग्रामीण स्तर पर क्षमताओं को बढ़ाने, योजनाओं और संसाधनों को मिलाकर विस्तार योग्य मॉडल बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और बाजार से जुड़ाव पर है। इसके लिए सीएसओ, सरकारी विभागों और एफपीओ को साथ लाकर जिला और ब्लॉक स्तर पर गठबंधन बनाए जाएंगे, ताकि कृषि–पर्यावरण के सिद्धांत क्षेत्रीय योजनाओं का हिस्सा बन सकें। शुरुआत में एक जिला गठबंधन बनाना, एसआरएलएम और कृषि विभागों को शामिल करना और पायलट ब्लॉकों की पहचान करना मुख्य कदम होंगेकृजिससे समावेशी, जलवायु–सहिष्णु और बाजार से जुड़े कृषि–पर्यावरण परिवर्तन की नींव रखी जा सके।

बीआरएलएफ विजन कार्यान्वयन

भारत के सतत विकास एजेंडे को सशक्त बनाना

हमारा काम भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ गहराई से मेल खाता है। यह समग्र प्रगति (होलीस्टिक प्रोग्रेस) पर जोर देता है, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरणीय प्रबंधन, सामाजिक समानता और संस्थागत मजबूती का एकीकरण (इंटीग्रेशन) शामिल है।

बीआरएलएफ के दृष्टिकोण का मूल (core) यह है कि ऐसे मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र (resilient ecosystems) को बढ़ावा दिया जाए जहाँ समुदाय जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ें (thrive)। सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs), केंद्र और राज्य सरकारों के निकायों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, और स्थानीय संस्थानों के साथ साझेदारी करके, बीआरएलएफ ग्रामीण कमजोरी के मूल कारणों को संबोधित करता है, साथ ही समुदाय–नेतृत्व वाले समाधानों को भी बढ़ावा देता है। हमारी गतिविधियाँ (Interventions) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा और असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) जैसे राज्यों के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली हुई हैं। अकेले वित्तीय वर्ष 2024.25 में, इन गतिविधियों का सीधा असर लगभग 3.50 लाख परिवारों पर पड़ा है।

बीआरएलएफ के कार्यक्रम चार मुख्य स्तंभों पर आधारित हैं, जो मिलकर सात प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करते हैं: गरीबी उन्मूलन(एसडीजी 1), भूख मिटाना(एसडीजी 2), लैंगिक समानता (एसडीजी 5), सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक विकास(एसडीजी 8), न्यूनतम असमानताएं (एसडीजी 10), जलवायु संरक्षण और लक्ष्यों के लिए साझेदारी (एसडीजी 17)। ये स्तंभ आर्थिक मजबूती, जलवायु अनुकूलन, संस्थागत सहयोग और प्रतिनिधित्व समुदायों के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस समन्वित दृष्टिकोण से परियोजनाएँ अलग नहीं बल्कि एक–दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जिससे स्थायी और प्रभावशाली गरीबी उन्मूलन के रास्ते तैयार होते हैं।

मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधियों, समुदाय की भागीदारी और सीएसओ विशेषज्ञता को मिलाकर बनाए गए समन्वय मॉडल के माध्यम से, बीआरएलएफ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है और अपने प्रभाव को व्यापक बनाता है। इस वर्ष हमारी पहलों ने पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया, आय के स्रोतों में विविधता लाई और महिलाओं तथा आदिवासी समुदायों को परिवर्तन की अगुवाई करने के लिए सशक्त किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समान और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखी गई। अगले अध्यायों में प्रत्येक स्तंभ का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो दिखाता है कि कैसे बीआरएलएफ अपने उद्देश्यों को ठोस और मापनीय परिणामों में बदलता है।

आर्थिक अनुकूलनता का सृजन – निचले स्तर को सुरक्षित करना

आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता एक पहल/गतिविधि मात्र नहीं है बल्कि यह एक बहु–स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें समुदायों को उनकी भूमि, जल और आजीविका पर नियंत्रण वापस पाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। बीआरएलएफ इस क्षेत्र में छोटे किसानों और वनों बढ़ावा, पशुपालन से आय का समर्थन और मजबूत सामूहिक संस्थाओं का निर्माण करके, बीआरएलएफ समुदायों को अस्थिर, जीविकोपार्जन आधारित जीवन से विविध और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है।

वर्ष 2024–25 में, हमारा दृष्टिकोण अभिसरण (Convergence) पर आधारित रहा, जिसका अर्थ है सरकारी योजनाओं, CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व), सामुदायिक योगदान और सिविल सोसाइटी भागीदारी से संसाधनों को एक साथ मिलाना। इस वर्ष की गई पहलों से न सिर्फ बंजर और खराब हो चुकी जमीनों को फिर से उपजाऊ बनाया गया, बल्कि हाशिये पर रह रहे लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर भी प्राप्त हुए।

सिंचाई और आजीविका परिसंपत्ति निर्माण

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक ही उत्पादक साधन–जैसे खेत की तालाब, सिंचाई कुआँ या पशुशाला–घर की क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे वे अपनी खेती को बेहतर बना सकें, आय के स्रोतों में विविधता ला सकें और स्थायी आजीविका सुनिश्चित कर सकें। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बीआरएलएफ की पहलों का मुख्य फोकस ऐसे महत्वपूर्ण साधनों के निर्माण को व्यापक स्तर पर बढ़ाने पर रहा। ये पहल केवल अवसंरचनात्मक काम नहीं थीं, बल्कि सहभागी प्रक्रियाएँ थीं, जिनमें समुदाय, सीएसओ और स्थानीय शासन निकाय मिलकर प्रत्येक परिवार की विशिष्ट आजीविका जरूरतों के अनुसार समाधान तैयार करते थे।

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और बोडोलैंड में, व्यापक वाटरशेड विकास और आजीविका वृद्धि पहल ने खेत तालाबों, चेक डैम और गेबियन संरचनाओं के निर्माण और कायाकल्प को जन्म दिया। इन परिसंपत्तियों ने जल प्रतिधारण और पुनर्भरण में काफी वृद्धि की, जिससे किसानों को वर्षा आधारित कृषि पर अपनी निर्भरता कम करने और कई फसल चक्रों की खेती करने में मदद मिली। इसी तरह, सिंचाई कुओं और पुनर्भरण गड्ढों के बड़े पैमाने पर विकास ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए साल भर पानी की पहुंच प्रदान की, जिससे पहले की परती भूमि का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित हुआ।

सभी राज्यों में परिवारों ने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें उत्पादक साधनों का निर्माण कई स्तरों पर व्यवस्थित करके किया गया, ताकि वे विविध आजीविका विकल्पों को सक्षम बना सकें। वर्षों के संघर्ष ने असम के बीटीआर में, आर्थिक स्थिरता को बाधित कर दिया था इस परियोजना ने बुनियादी आजीविका के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था – 1,100 से अधिक परिवारों को कुओं, आश्रयों, बागों और खेत तालाबों जैसी आवश्यक परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ समर्थन दिया गया था, इनमें से 80% से अधिक परिवारों ने बाद में इन परिसंपत्तियों के आसपास कई आजीविका गतिविधियों को अपनाया।

सभी परियोजना क्षेत्रों में, बीआरएलएफ का उत्पादक साधन निर्माण मॉडल 'समन्वय' पर आधारित रहा, जिसमें मनरेगा जैसी योजनाओं और विभिन्न सरकारी विभागों–जैसे बागवानी और मत्स्य पालन–के संसाधनों का उपयोग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे साधन तैयार करना था जो समुदाय के स्वामित्व वाले, वास्तविक जरूरतों पर आधारित और तकनीकी रूप से मजबूत हों, ताकि परियोजना की अवधि के बाद भी उनकी स्थिरता बनी रहे।

मुख्य डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

1,17,021
आजीविका परिसंपत्तियों के साथ समर्थित परिवार

1,05,211
सिंचाई के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)

1,983
बनाए गए वाटरशेड संरचनाओं की संख्या (तालाब, चेक डैम, आदि)

3,982
मिट्टी और नमी संरक्षण संरचनाओं की संख्या

1,016
मृदा और नमी संरक्षण संरचनाओं के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

980
निर्मित सिंचाई कुओं की संख्या

95
वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों के साथ समर्थित परिवार

570
हथकरघा में लगे परिवार

219
रेशम उत्पादन में लगे परिवार

"अब मैं खुश हूँ। पहले मैं खुश नहीं था।" छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संदेओदा गाँव के किसान दालिमचंद कश्यप की भावनाएँ उनके इन सरल शब्दों में सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त होती हैं। पर्याप्त बारिश न होने और आसपास पानी के स्रोत न होने के कारण पहले सिंचाई के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन, खेत में तालाब (Farm Pond) बनवाने के बाद, उनकी फसल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई और इसके साथ ही उनकी आय भी बढ़ी।

दालिमचंद की तरह, कई और किसान इन तालाबों से लाभान्वित हुए हैं। ये तालाब खेती के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं जो साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। तालाब बनाने के अलावा, इन किसानों को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। ये योजनाएँ उन्हें टपक सिंचाई प्रणाली (drip irrigation), सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप, खेत की मेड़ें (farm bunds), मछली के बीज (fishlings), सब्सिडी वाले बीज आदि उपलब्ध कराकर उनकी संपत्तियों को और मजबूत करती हैं, जिससे किसानों की आर्थिक मजबूती (economic resilience) बढ़ती है।

एकीकृत और विविध कृषि प्रणालियाँ

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए एकल फसलों (Monocropping) से आगे बढ़कर एकीकृत और विविधीकृत खेती की ओर बढ़ना आर्थिक सुरक्षा की राह है। बीआरएलएफ के हस्तक्षेप इस बदलाव को संभव बनाने पर केंद्रित रहे हैं–जहाँ व्यवस्थित फसल योजना, उच्च मूल्य वाली फसलें, बागवानी, पोषण वाटिका और एकीकृत खेती प्रणाली (IFS) के मॉडल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें फसलों के साथ पशुपालन, पोल्ट्री और मत्स्यपालन को भी जोड़ा गया है।

ओडिशा में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर (APC) कार्यक्रम के अंतर्गत 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उच्च मूल्य वाली फसलों के अंतर्गत लाया गया है और 6,900 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बागवानी एवं फलदार वृक्षों के रोपण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही पशु आश्रय और सामुदायिक स्तर के एकत्रीकरण केंद्र जैसे विविध आजीविका संसाधन भी विकसित किए गए हैं। झारखंड में एकीकृत खेती प्रणाली (IFS) को व्यापक रूप से लागू किया गया है, जहाँ 4,200 से अधिक कृषि–उद्यमी बागवानी, पशुपालन और जैविक खाद/इनपुट उत्पादन जैसी विविध गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

महाराष्ट्र में वाटरशेड परियोजनाओं के तहत रसोई और पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिया गया है, जिससे महिलाओं को न केवल परिवार की पोषण जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है बल्कि अतिरिक्त उत्पादन से बाजार में बिक्री का अवसर भी मिला है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR), असम में, जो परिवार पहले मजदूरी पर निर्भर थे, वे अब नव–निर्मित संसाधनों के इर्द–गिर्द मौसमी फसलें, सब्जियाँ और पिछवाड़े की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आय और खाद्य उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इस एकीकृत और विविधीकृत खेती पद्धति ने न सिर्फ खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया है बल्कि आय के कई स्रोत तैयार कर किसानों को मजबूत बनाया है, जिससे वे जलवायु और बाजार से जुड़ी अनिश्चितताओं का बेहतर सामना कर पा रहे हैं।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

1,05,211
कृषि आदानों के साथ समर्थित परिवार

51,350.48
उच्च मूल्य वाली फसलों के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर में)

1,621.21
विकसित बाग क्षेत्र (हेक्टेयर में)

4,938
किचन गार्डन/सब्जी भूखंडों वाले घर

1,250
बाग–बगीचे की पहल में महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार

झारखंड के खुंटपानी के एक सीमांत किसान, लबेया जोंको बताते हैं, **"जब से मैंने एकीकृत खेती प्रणाली (IFS) मॉडल अपनाया है, मेरा मुनाफा बढ़ गया है।"**

लबेया अब अपने खेत के तालाब की मेड़ों पर तरह–तरह की सब्जियाँ उगाते हैं, साथ ही तालाब का इस्तेमाल मछली पालन (पिसिकल्चर) और बत्तख पालन के लिए भी कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने अलग–अलग सब्जियाँ उगाने के लिए एक मचान (Scaffold Farming) भी लगा रखा है। खेती के इस एकीकृत तरीके से न सिर्फ उनकी कृषि पद्धतियों में विविधता आई है, बल्कि उनकी आय में भी अच्छी–खासी बढ़ोतरी हुई है।

भविष्य को लेकर लबेया काफी महत्वाकांक्षी हैं। वह विश्वास के साथ कहते हैं, **"आने वाले 2–3 सालों में, मैंने सालाना 4 से 5 लाख रुपये कमाने का लक्ष्य रखा है।"**

पशुधन और मुर्गी पालन आधारित आजीविका

ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ खेती मौसमी होती है और जलवायु सम्बंधित अनअपेक्षित हालातों से बहुत प्रभावित रहती है, पशुपालन और पोल्ट्री आधारित आजीविका छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनती है। बीआरएलएफ ने अपनी परियोजनाओं के अंतर्गत इन गतिविधियों को विविधीकृत आजीविका का अभिन्न हिस्सा बनाने पर विशेष ध्यान दिया है।

झारखंड और ओडिशा में बैकयार्ड पोल्ट्री एवं बकरी पालन पर जोर रहा है, जिन्हें महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों के लिए कम लागत और आसानी से बढ़ाए जा सकने वाले मॉडल के रूप में माना गया। इसके अंतर्गत चूजों और बकरियों का वितरण, चारे की उपलब्धता, टीकाकरण, कृमिनाशन सेवाएँ और रोग प्रबंधन व आश्रय संबंधी प्रशिक्षण शामिल रहे। समय के साथ यह पहल केवल संसाधन उपलब्ध कराने तक सीमित न रहकर उद्यम विकास तक पहुँची, जहाँ महिलाएँ उत्पादक समूह बनाकर सामूहिक रूप से चारा व अन्य सामग्री खरीदने और स्थानीय बाजार तक पहुँचने लगीं।

महाराष्ट्र में गाय और बकरी पालन को आश्रय ढाँचे और चारे की उपलब्धता सुधारकर बढ़ावा दिया गया, जिसे पशु–चिकित्सा सेवाओं का सहयोग भी मिला। वहीं, बीटीआर (असम) में उन परिवारों के बीच पशु आश्रय और बैकयार्ड पोल्ट्री मॉडल को प्रोत्साहित किया गया जो पहले केवल जीविका–आधारित खेती पर निर्भर थे। इससे उनकी आय बढ़ी और मजदूरी के लिए पलायन की समस्या कम हुई। यहाँ विशेष रूप से वैज्ञानिक ढंग से सुअर और बकरी पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

साथ ही, पशु स्वास्थ्य, प्रजनन तकनीक और चारा प्रबंधन पर क्षमता–विकास इस पूरी पहल का केंद्रीय आधार रहा, जिससे ये पहल सतत बनी और समय के साथ परिवारों की आय में स्थिर और निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हो सकी।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25 और संचयी/कुल)

96,117
मुर्गी पालन/पशुधन के साथ समर्थित परिवार

110
पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए

3,040
बकरी शेड/पोल्ट्री शेड/पिग शेड/चारा इकाइयों का निर्माण किया गया

असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के तमुलपुर ब्लॉक में स्थित डुमुरिया गाँव में, "रिमझिम" स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्य मैदंगश्री बोरो ने अपनी आजीविका में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अपने पति के दूसरे राज्य में काम करने के साथ, 30 वर्षीय ने दिसंबर 2023 में एक सुअर पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर अपने परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी संभाली।

कम लागत वाले सुअर पालन, उचित भोजन और समय पर टीकाकरण के ज्ञान से लैस, मैदंगश्री ने अपना सुअर पालन शुरू करने के लिए 15,000 रुपये का निवेश किया। अगस्त 2024 तक, उसके दो सूअरों ने 21 सूअरों को जन्म दिया था। उन्होंने 17 सूअरों को 4,000 रुपये में बेचा, जिससे कुल 68,000 रुपये की कमाई हुई। अपनी सफलता से प्रेरित होकर, उसने अपने सुअर पालन का विस्तार किया और छह सूअरों को रखने के लिए अपने शेड का पुनर्निर्माण किया।

सुअर पालन के अलावा, मैदंगश्री ने कृषि विभाग द्वारा प्रदान किए गए बीजों के साथ एसआरआई पद्धति का उपयोग करके सब्जी की खेती और चावल की खेती के माध्यम से अपनी आय में विविधता ला पाई। कभी आजीविका के अवसरों से अनजान रही मैदंगश्री की सफलता यह दर्शाती है कि प्रशिक्षण और सहयोग किस तरह जीवन बदलने वाली ताकत बन सकते हैं।

सामूहिक कृषि, उत्पादक समूह और ग्रामीण उद्यम

हालाँकि परिवार स्तर पर संसाधन निर्माण और आजीविका का विविधीकरण महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक कदम हैं, लेकिन स्थायी ग्रामीण परिवर्तन तभी संभव है जब छोटे किसान सामूहिक रूप से संगठित होकर बाजार तक पहुँचें और अपनी सौदेबाजी क्षमता बढ़ाएँ। इसे ध्यान में रखते हुए, बीआरएलएफ ने परियोजना क्षेत्रों में उत्पादक समूह (PGs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और ग्रामीण उद्यमों के गठन और सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है। ये संस्थाएँ ऐसे आर्थिक मंच का काम करती हैं जो समुदायों को केवल जीविका–आधारित खेती से आगे बढ़ाकर बड़े पैमाने पर संगठित संचालन की ओर ले जाती हैं।

छत्तीसगढ़ में 40,000 से अधिक परिवारों को उत्पादन क्लस्टरों के अंतर्गत पीजी में संगठित किया गया है। इससे किसान सामूहिक रूप से कृषि सामग्री की खरीद, उत्पादन का संकलन और विपणन कर पा रहे हैं। इस मॉडल से न केवल लागत घटी है, बल्कि छोटे–स्तर के प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए मूल्य संवर्धन भी संभव हुआ है। ओडिशा में एपीसी कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2024–25 में 11,995 से अधिक परिवारों को महिला–नेतृत्व वाले पीजी में जोड़ा गया, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 1,34,886 परिवार हो गई। इन्हें बागवानी, दलहन और वन–उत्पादों (NTFPs) की मूल्य शृंखलाओं से भी जोड़ा गया। इसके साथ ही, बीआरएलएफ ने वन धन योजना जैसी सरकारी योजनाओं से अभिसरण कर आदिवासी परिवारों को कौशल विकास और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया, जिससे वे वन–आधारित उद्यमों में आगे बढ़ सके।

अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादक समूह छोटे किसानों के लिए उचित मूल्य दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सब्जियों का सामूहिक संकलन, सामूहिक इनपुट खरीद और स्थानीय बाजारों से जुड़ाव जैसी गतिविधियों ने किसानों, विशेषकर महिलाओं, को सामूहिक आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति दी है। छोटे और सीमांत किसान, जो पहले मूल्य शृंखला में अलग–थलग पड़े थे, अब संगठित मंचों का हिस्सा बनकर खरीदारों तक पहुँच बना रहे हैं, बिचौलियों के शोषण से बच रहे हैं और उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

56,209
एनटीईएफपी–आधारित आजीविका में लगे परिवार

31
एफपीओ को बढ़ावा/सहयोग दिया गया

287
कृषि–उद्यमियों का सहयोग

654
उत्पादक समूहों का गठन/सक्रिय

78,29
सामूहिक बिक्री का मूल्य (₹ करोड़ में)

268
लखपति परिवार

"मैंने अपने पैसे से एक स्कूटर खरीदा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है,"
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक के कोचवाही गाँव की 33 वर्षीय आदिवासी महिला, शिवकुंवर कोरेटी कहती हैं। 2016 में, न केवल अपने जीवन में, बल्कि अपने समुदाय की अन्य महिलाओं के जीवन को भी बेहतर बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर, शिवकुंवर जय बुडादेव स्वयं सहायता समूह में शामिल हो गई। शुरू में शर्मीली और झिझकने वाली, उन्होंने धीरे–धीरे प्रशिक्षण और परियोजना पहल से सहयोग मिलने से आत्मविश्वास हासिल किया।

2019 तक, उन्होंने मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) योजना प्रक्रिया में लीडर की भूमिका निभाई, अपने गाँव में भूमि और जल संपत्ति के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया। अपने परिवार के समर्थन से, उन्होंने सिंचाई के बुनियादी ढांचे को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न केवल अपने परिवार की आजीविका में सुधार किया, बल्कि समुदाय की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया।

जलवायु-संवेदी ग्रामीण विकास - अनुकूलन संवर्द्धन और संतुलन की पुनर्स्थापना

बढ़ती जलवायु चुनौतियों और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के बीच, बीआरएलएफ की इस श्रेणी की पहलों का लक्ष्य पर्यावरण और आर्थिक स्थिरता दोनों को मजबूत करना रहा। समेकित वाटरशेड प्रबंधन, बिना कीटनाशक प्रबंधन (NPM) और प्राकृतिक खेती, कृषि व सामुदायिक पौधरोपण जैसी गतिविधियों ने मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने, जल सुरक्षा बढ़ाने और प्रकृति–समर्थ खेती को प्रोत्साहित किया। मिट्टी और जल संरक्षण, जल संचयन ढाँचे और कृषि–वनीकरण (Agroforestry) के माध्यम से 1.3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपचार किया गया, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए दीर्घकालिक उत्पादकता और स्थायित्व सुनिश्चित हुआ। विभिन्न राज्यों में सामुदायिक संस्थाएँ, विशेषकर महिला समूह, जलवायु–अनुकूल योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदार बनीं। गैर–कीटनाशक प्रबंधन, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और देशी प्रजातियों की खेती को अपनाने से खेती का स्वरूप बदला और यह कम–लागत, अधिक–लचीलेपन वाले सतत कृषि मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

वाटरशेड और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम)

बीआरएलएफ की वाटरशेड और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पहल अवक्रमित परिदृश्य को बहाल करने, जल सुरक्षा में सुधार करने और वर्षा सिंचित और जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन प्रयासों में मिट्टी और नमी संरक्षण (एसएमसी) उपायों, खेत तालाबों और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और दोहरी फसल व सिंचाई क्षमता के लिए भूमि उपचार शामिल हैं, जो सीधे दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आजीविका लचीलापन में योगदान करते हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, हजारों हेक्टेयर भूमि को वाटरशेड और भूमि और जल संसाधन संरक्षण के तहत उपचारित किया गया, जबकि जल संचयन संरचनाओं ने सिंचाई क्षमता में काफी वृद्धि की। स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से सीमांत और महिला किसानों ने इन प्रयासों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पहलों ने कटाव को रोकने, भूजल पुनर्भरण में सुधार करने और बहु–मौसमी खेती की नींव रखने में मदद की।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

17,659.87 हेक्टेयर
वाटरशेड/एनआरएम के तहत उपचारित भूमि

15,663
खेत तालाबों का निर्माण

2,291
निर्मित जल संचयन/संरक्षण संरचनाएँ

11874.07 हेक्टेयर
कुल सिंचाई क्षमता का सृजन

15,915.03 हेक्टेयर
भूमि और जल संसाधन संरक्षण के तहत उपचारित क्षेत्र

8,565.95 हेक्टेयर
दोहरी फसल और दीर्घकालिक वनस्पति के लिए निर्मित कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)

6,978
भूमि और जल संरक्षण गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले परिवार

52 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी छोटी सब्जी खेती को एक पूरा व्यवसाय बना पाऊँगा। मैं किशन हूँ, यवतमाल, महाराष्ट्र के अष्टी गाँव से। यहाँ की जमीन पहाड़ी, जंगलों से भरी और मुश्किल है। पहले मैं बैंगन, मिर्च और पालक उगाता था, तभी 2024 में हमारे ब्लॉक में हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट (HIMWP) आया। सही मार्गदर्शन मिलने पर मैंने अपनी फसलों में विविधता लानी शुरू की, सतत खेती के तरीके अपनाए और अपने खेत का विस्तार दो एकड़ तक कर लिया। अब मैं मक्का, मेथी, तुरई और अन्य फसलें उगाता हूँ और सब बिना रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक के। मेरी रोजाना सब्जियों की बिक्री से ₹300–₹400 की आमदनी होती है और केवल मिर्च से सालाना ₹20,000 तक की आय होती है। अब मेरा बेटा भी मेरा साथ देता है और हमारे खेत हमारा साझा भविष्य बन गए हैं।

वृक्षारोपण, कृषि वानिकी और पुनर्वनीकरण

बीआरएलएफ की वृक्षारोपण और कृषि वानिकी पहल का उद्देश्य खराब भूमि को बहाल करना, जलवायु बफर बनाना और आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए दीर्घकालिक आजीविका के अवसर पैदा करना है।

जैसे–जैसे भारत के ग्रामीण परिदृश्यों में जलवायु परिवर्तनशीलता तेज हो रही है, वृक्षारोपण और कृषिवानिकी–आधारित पहलों के लिए बीआरएलएफ का समर्थन समुदायों को पारिस्थितिक बफर बनाने और दीर्घकालिक आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद कर रहा है। परियोजना भौगोलिक क्षेत्रों में समुदाय सक्रिय रूप से वृक्षारोपण अभियान, बंड वृक्षारोपण और बाग विकास में लगे हुए थे। ये हस्तक्षेप मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं और गैर–लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) और बागवानी फसलों के माध्यम से अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करते हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कई भौगोलिक क्षेत्रों में 1,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाग विकास के तहत लाया गया। महिलाओं की भागीदारी में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया, जिसमें 500 से अधिक महिला नेतृत्व वाले परिवार सीधे तौर पर बाग और वृक्षारोपण पहल में लगे हुए हैं, जिससे आय विविधीकरण और पोषण सुरक्षा दोनों में वृद्धि हुई है।

कृषि वानिकी प्रथाओं को स्थानीय कृषि–जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित किया गया थारू ओडिशा और महाराष्ट्र में, बागवानी वृक्षारोपण को जल संरक्षण संरचनाओं के साथ एकीकृत किया गया था, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में, एनटीएफपी वाली प्रजातियों जैसे महुआ और इमली को सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था। सतत और सहभागी मॉडल पर जोर दिया गया, जिन्हें अक्सर सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से सह–वित्तपोषित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के शंकरगढ़ में, बलवंत ने उत्साह से कहा, **"अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो ये पेड़ मुझे आमदनी देंगे।"** जब हम उनके घर गए, तो उन्होंने हमें अपना खेत दिखाया जहाँ उन्होंने छोटे–छोटे पौधों की कतारें लगा रखी थीं। हालाँकि ये पेड़ अभी बचपन की अवस्था में हैं, फिर भी ये बलवंत के लिए उत्साह और आशा का स्रोत हैं।

बलवंत ने सागौन, चंदन और नीलगिरी समेत 700 पेड़ लगाए हैं और उनकी देखभाल के लिए उन्हें सरकार से थोड़ा–सा वजीफा (stipend) भी मिलता है। यह सब मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के जरिए संभव हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ वन विभाग की एक पहल है। इस योजना का लक्ष्य व्यावसायिक पेड़ लगाने में किसानों का सहयोग करके उनकी आय बढ़ाना है। यह योजना लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और न्यूनतम मूल्य पर लकड़ी की खरीद की गारंटी देने का भी प्रयास करती है। इस पूरी लागत को वन विभाग और निजी बोली लगाने वाले (private bidders) साझा करते हैं।

जलवायु–अनुकूल कृषि

कृषि वानिकी के तहत क्षेत्र	वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र	बागों और बंड वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र	बागवानी के तहत परिवार
1,809.61 हेक्टेयर	4,50.13 हेक्टेयर	1,722.33 हेक्टेयर	97,135

जलवायु–अनुकूल कृषि

बीआरएलएफ द्वारा समर्थित पहलें कृषि के ऐसे मॉडल को आगे बढ़ा रही हैं जो जैविक, कम लागत वाला और जलवायु–स्मार्ट है। यह मॉडल अल्पावधि लाभ की जगह स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) को प्राथमिकता देता है। इन प्रयासों का मुख्य ध्यान ऐसी पद्धतियों पर है जो छोटे किसानों के लिए भोजन और आय सुनिश्चित करने के साथ–साथ पारिस्थितिक संतुलन को भी बहाल करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, प्राकृतिक खेती और गैर–कीटनाशक प्रबंधन (NPM) तकनीकों को अपनाने वाले परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से बड़ी संख्या में परिवारों को वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ, गुणवत्तापूर्ण बीज, और जैव–विकर्षक (bio&repellents) जैसे जरूरी इनपुट (सामग्री) देकर मदद की गई। ओडिशा और महाराष्ट्र में, कृषि विस्तार अभियानों ने कम्पोस्टिंग और फसल चक्रण द्वारा मिट्टी को समृद्ध करने को बढ़ावा दिया। झारखंड में, एकीकृत खेती प्रणाली (IFS) मॉडल, जिसमें पशुधन, मत्स्य पालन और फसल उत्पादन को मिलाया जाता है, ने रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करते हुए संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में मदद की। इन जलवायु–अनुकूल (climate-resilient) पद्धतियों ने किचन गार्डन और पारिवारिक स्तर पर पोषण पर भी जोर दिया। इससे न केवल आहार विविधता में सुधार हुआ, बल्कि परिवारों को बाजार की अस्थिर कीमतों से भी सुरक्षा मिली।

किसानों को जलवायु जागरूकता सत्रों द्वारा भी प्रशिक्षित किया गया, जिससे प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और जलवायु जोखिमों के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम करने की क्षमता में सुधार आया।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

33,381.69 हेक्टेयर
एनपीएम/प्राकृतिक खेती कृषि के तहत क्षेत्र

57,684
एनपीएम–आधारित कृषि के तहत परिवार

2019 में, ओडिशा के जैपदा गाँव की टिकेश्वरी पटेल ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया – रासायनिक खेती को पीछे छोड़ने और जैविक प्रथाओं को अपनाने का। **"पहले, रासायनिक खेती हमें भारी पड़ती थी और पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाती थी। एक बार जब मैंने इसके प्रभाव को समझा, तो मैंने जैविक खेती पर स्विच करने का दृढ़ निश्चय किया,"** वह याद करती हैं।

उनके गाँव में सात स्वयं सहायता समूहों सहित 70 सदस्यों के साथ एक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) के गठन ने नए दरवाजे खोले। एफपीसी के माध्यम से, उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में सीखा, जैविक तरीकों पर प्रशिक्षण में भाग लिया और सतत तकनीकों को अपनाया। इस बदलाव ने न केवल उनकी कमाई में वृद्धि की, बल्कि उन्हें पहचान भी मिली जब उन्हें एक एकड़ भूमि पर बाजरा की खेती के लिए सम्मानित किया गया – गर्व का एक ऐसा क्षण जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टिकेश्वरी की सफलता ने न केवल उनकी पारिवारिक आय में सुधार किया है, बल्कि उनके गाँव के 72 अन्य किसानों को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे वह सतत कृषि की सच्ची चौंपियन बन गई हैं।

सिस्टम, संस्थाएँ और साझेदारी – स्थायी परिवर्तन के लिए मजबूत आधार

सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केवल जमीन स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि मजबूत संस्थागत ढांचे, सक्षम साझेदारी और ऐसे लचीले सिस्टम भी जरूरी हैं, जो समाधान को बड़े पैमाने पर लागू कर सकें। इस श्रेणी के अंतर्गत, बीआरएलएफ ने शासन प्रणाली को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय सक्षम करने, नागरिक समाज संगठनों की क्षमता बढ़ाने और सीखने, नवाचार और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बीआरएलएफ ने कई राज्यों में प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों जैसे मनरेगा और मिशन शक्ति के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पहलों की वजह से अलग–अलग विभागों से 526.68 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई, जिससे गाँवों में विकास योजनाएँ ज्यादा संगठित और असरदार बनीं। साथ ही, विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन को गाँव स्तर पर भी बेहतर तरीके से समन्वित किया गया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में राज्य विभागों के साथ समझौते (MoUs) किए गए, जिससे संस्थागत सहयोग और गहरा हुआ। बीटीआर (असम) और ओडिशा में जिला प्रशासन ने नियमित फील्ड विजिट और योजना समीक्षा आयोजित की, जिसमें CSOs और PRI पदाधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए।

इस श्रेणी के तहत क्षमता निर्माण बीआरएलएफ के प्रयासों का मूल स्तंभ रहा। 7,000 से अधिक हितधारकों—including ग्राम रोजगार सेवक, स्व–सहायता समूह (SHG) नेता, CSO स्टाफ और सरकारी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताकृको विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: जलग्रहण क्षेत्र विकास, MIS, जैविक खेती, GIS–आधारित DPR तैयारी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशुपालन प्रबंधन और अधिकारों की डिलीवरी। इन प्रशिक्षणों ने ग्रामीण संस्थाओं की तकनीकी और नेतृत्व क्षमता बढ़ाई और ऐसी योजना तैयार करने में मदद की, जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को दर्शाती हो।

बीआरएलएफ ने छत्तीसगढ़ में Participatory Digital Attestation (PDA) जैसे नवाचारी उपकरणों का परीक्षण भी किया, जिससे वास्तविक समय में निगरानी और साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने की सुविधा मिली। नियमित समन्वय बैठकें, क्रॉस–लर्निंग विजिट और अनुभव आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से, इस वर्ष का कार्य अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और सहयोगात्मक ग्रामीण शासन प्रणाली की नींव रखने में सफल रहा।

सरकारी योजनाओं का तालमेल और संस्थागत भागीदारी

बीआरएलएफ की रणनीति का मुख्य आधार संस्थाओं और सरकार के साथ मिलकर सिस्टम में बदलाव लाना है। सरकारी योजनाओं के साथ परियोजना योजना को जोड़कर, बीआरएलएफ ने बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग संभव बनाया, कार्यान्वयन की समय–सीमा को संगठित किया और विभिन्न राज्यों में पहलों के भौगोलिक और कार्यात्मक दायरे का विस्तार किया।

इस वर्ष राज्य और जिला दोनों स्तरों पर औपचारिक साझेदारी को गहरा किया गया। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, बीआरएलएफ ने मनरेगा और पोकरा (जलवायु अनुकूल खेती परियोजना) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिससे 335 गांवों में अभिसरण की सुविधा मिली और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के संयुक्त कार्यान्वयन को सक्षम किया गया। ओडिशा में आईटीडीए, आईसीआरआईसैट, ओएलआईसी और मिशन शक्ति जैसे विभागों के साथ मिलकर 115.5 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई। बीटीआर, असम और छत्तीसगढ़ में, जिला अधिकारियों के साथ सहयोगात्मक योजना के मॉडल को दोहराया गया, जिससे डीपीआर निष्पादन और निगरानी में बहु–विभागीय भागीदारी सुनिश्चित हुई। राज्यों में, इन प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि स्थानीय जरूरतों को सबसे उपयुक्त योजनाओं के साथ मिलाया जाए, दोहराव से बचा जाए और विकास के प्रभाव को अधिकतम किया जाए।

इस तरह के अभिसरण ने न केवल बुनियादी ढांचे और आजीविका के लिए धन जुटाने में सक्षम बनाया, बल्कि सीएसओ और सरकारी एजेंसियों के बीच जवाबदेही और सुव्यवस्थित समन्वय में भी सुधार किया। इन साझेदारियों को नियमित संयुक्त बैठकों, क्षेत्र की समीक्षा और योजना अभ्यासों के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया था, जो ग्रामीण विकास में अधिक उत्तरदायी और सहभागी शासन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

22
जुड़े सरकारी विभाग (एमओयू या अभिसरण)

526.68
कुल सरकारी फंड से प्राप्त लाभ

796
बाजार प्रणाली में किए गए सक्षम (मंडी, संस्थागत खरीदार, प्रसंस्करण केंद्र)

डाइवर्सिफिकेशन विद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल्स लाइव्स (DWIMU) परियोजना को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) सरकार द्वारा विशेष मान्यता मिली। यह मान्यता हमारे सहयोग की मजबूती और जमीनी स्तर पर हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। हम बीटीआर सरकार और माननीय सीईएम श्री प्रमोद बोरों के निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के लिए आभारी हैं। यह पहचान हमें और अधिक उत्साह के साथ बीटीआर की जनता के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए काम करने की प्रेरणा देता है, ताकि मिलकर एक उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य का निर्माण किया जा सके।

स्थानीय शासन, सीएसओ और क्षमताओं को मजबूत करना

वर्षों से बीआरएलएफ ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करने और अंतिम छोर तक विकास पहुँचाने में एक प्रेरक सहयोगी की भूमिका निभाता रहा है। वित्त वर्ष 2024–25 में यह दृष्टिकोण विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय हुआ, जहाँ सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) को ग्राम सभाओं, पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए व्यवस्थित रूप से सहयोग दिया गया।

बीआरएलएफ का जमीनी शासन को सशक्त बनाने पर ध्यान कई रूपों में दिखाकृसमुदाय संसाधन व्यक्तियों (CRPs) और फील्ड फैसिलिटेटरों का प्रशिक्षण, उत्पादक समूहों (PGs), एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के नेतृत्वकर्ताओं की क्षमता–वृद्धि। ओडिशा और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पीजीध्एफपीओ नेताओं और पंचायत स्तर की टीमों को प्रशिक्षित किया गया ताकि नीचे से ऊपर की ओर योजना बनाई जा सके। बीटीआर, असम और झारखंड में सीएसओ को मार्गदर्शन दिया गया ताकि वे ग्राम सभाओं के साथ मिलकर संवेदनशीलता आकलन और सूक्ष्म–योजनाएँ बना सकें और निर्णय प्रक्रिया अधिक सहभागी हो। सीएसओ को सहयोग और मार्गदर्शन देना बीआरएलएफ का एक केंद्रीय स्तंभ रहा, जिसके तहत वर्षभर विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों के जरिए साझेदार संगठनों को नए अनुभव सीखने और अपनी रणनीतियों को अनुकूल बनाने का अवसर मिला। इन प्रयासों से न केवल परियोजना क्रियान्वयन में सुधार हुआ, बल्कि समुदाय की भागीदारी बढ़ी, सरकारी विभागों से बेहतर तालमेल हुआ और महिलाओं व आदिवासी समुदायों की आवाज स्थानीय शासन में और मजबूत हुई।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

6,025
आयोजित प्रशिक्षण (पीजी / एफपीओ, सरकार / लाइन विभाग के अधिकारी, आदि)

56
सहयोग या सलाह दिए गए सीएसओ

महाराष्ट्र परियोजना को वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट (WOTR) की ओर से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर हमारे बहुमूल्य सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। यह सम्मान हमारी साझेदारी की मजबूती और उन सकारात्मक बदलावों को दर्शाता है, जो सबसे वंचित और आदिवासी क्षेत्रों में लाए जा रहे हैं। हम WOTR के आभारी हैं कि उन्होंने सतत विकास पहलों को आगे बढ़ाने और समुदाय–आधारित प्रभावी परिवर्तन सुनिश्चित करने में हमारे सतत समर्पण, रणनीतिक मार्गदर्शन और संसाधन सहयोग को मान्यता दी। यह सम्मान हमें प्रेरित करता है कि हम आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के जीवन और आजीविका को और बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें और मिलकर एक सतत भविष्य की दिशा में काम करें।

लर्निंग, साक्ष्य और नवाचार के लिए व्यवस्थाएँ

बीआरएलएफ का ग्रामीण विकास कार्य केवल जमीनी स्तर की पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ज्ञान–आधारित प्रणालियाँ भी तैयार करता है जो नीतियों और अभ्यास को दिशा देती हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में खास जोर क्षेत्रीय अनुभवों को दर्ज करने, प्रमाण–आधारित ज्ञान सामग्री विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर रहा, ताकि कार्यक्रमों का प्रभाव और मजबूत हो सके।

सभी परियोजना राज्यों में फील्ड मैनुअल, सूचना–शिक्षा–संप्रेषण (IEC) सामग्री और विषयगत अध्ययन जैसे ज्ञान उत्पाद तैयार किए गए, जिनमें जलागम प्रबंधन, जैविक/एनपीएम खेती और महिला–नेतृत्व वाले उद्यमों की अच्छी प्रथाओं को दर्ज किया गया। इन्हें सीएसओ साझेदारों, सरकारी विभागों और स्थानीय संस्थाओं तक पहुँचाया गया, जिससे उनकी तकनीकी और संचालन क्षमता मजबूत हुई।

इस वर्ष तकनीक और आँकड़ा–आधारित प्रणालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य–विशिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) को अंतिम रूप दिया गया, जिसने प्रमुख पहलों के लिए रीयल–टाइम निगरानी और बेहतर रिपोर्टिंग को संभव बनाया। साथ ही, आधारभूत अध्ययन और प्रभाव मूल्यांकन किए गए ताकि घरेलू आय, कृषि उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता में हुए बदलाव मापे जा सकें। इन अध्ययनों ने रणनीतियों को और परिष्कृत करने तथा समुदायों और संस्थागत साझेदारों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद की।

इसके अलावा, बीआरएलएफ ने ज्ञान–साझाकरण मंचों और नीतिगत संवादों में निवेश किया, जिनमें शोध सारांश और नीति नोट्स सरकारी हितधारकों को प्रस्तुत किए गए। इन पहलों ने न केवल आदिवासी और वंचित समुदायों की आवाज को मजबूती दी, बल्कि आजीविका, समन्वय और सतत ग्रामीण विकास से जुड़ी नीतियों को आकार देने में भी योगदान दिया।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

58
ज्ञान उत्पाद
(आईईसी सामग्री, सर्वेक्षण, प्रकाशन, रिपोर्ट, आदि)

2
शुरू किए गए आधारभूत अध्ययनों की संख्या

4
सरकार के साथ साझा किए गए शोध ब्रीफ/पॉलिसी नोट्स की संख्या

5
राज्य–विशिष्ट एमआईएस की संख्या को अंतिम रूप दिया गया

1
शुरू किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों की संख्या

"छत्तीसगढ़ के हाई इम्पैक्ट मेगा वॉटर्सेड प्रोजेक्ट में बीआरएलएफ द्वारा बनाए गए संकेत ऐप के साथ काम करना हमारे लिए डाटा संग्रहण को बहुत आसान और सुगम बना दिया है। घर–घर के डाटा की मंजूरी प्रक्रिया और फील्ड में वास्तविक समय पर जानकारी देख पाना अब बहुत तेज हो गया है। इसका तेज और सटीक स्थान निर्धारण हमारे काम के लिए बेहद उपयोगी है। ऐप में पूछे गए सवाल हमारे बेसलाइन सर्वे और योजना बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी और सही होते हैं। पहले एमआईएस का काम करते समय बेसलाइन डाटा भरने में बहुत समय लगता था और हमेशा शुद्धता की चिंता बनी रहती थी। संकेत ऐप ने वह चिंता दूर कर दी है और अब हमें अपने लक्ष्य सटीकता के साथ पूरा करने का आत्मविश्वास मिला है।"

— **श्री रवि कुमार,** एमआईएस विशेषज्ञ, सहभागी समाज सेवी संस्था, छत्तीसगढ़

महिलाओं और वंचितों को सशक्त बनाना: बाधाएँ हटाओ, क्षमता बढ़ाओ

भारत के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और वंचित समुदाय अक्सर ऐसे सिस्टमिक बाधाओं का सामना करते हैं, जो उनके निर्णय लेने और संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता को सीमित करती हैं। बीआरएलएफ का यह कार्य इन बाधाओं को तोड़ने और ऐसे मंच तैयार करने पर केंद्रित है, जहाँ महिलाएं और वंचित समूह बदलाव की अगुवाई कर सकें। इसका मतलब है उन्हें समुदायिक संस्थाओं में नेतृत्व की भूमिका देने, उनके अधिकार और लाभ तक पहुँच बढ़ाने और लक्षित क्षमता निर्माण और अवसरों के माध्यम से उनकी आर्थिक सशक्तता बढ़ाने का काम करना।

बीआरएलएफ परियोजनाओं के कुल लाभार्थियों में 70: से अधिक अनुसूचित जनजातियों से हैं, जो संगठन की समावेशिता और समानता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024–25 में इन प्रयासों से मजबूत जमीनी संस्थाएँ बनीं, स्थानीय शासन संरचनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, भूमि और संसाधनों तक पहुँच बेहतर हुई और आजीविका के अवसरों पर नियंत्रण मजबूत हुआ।

संरचनात्मक असमानताओं को दूर करके, इस श्रेणी में बीआरएलएफ के हस्तक्षेप केवल आजीविका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय अपने विकास को लंबे समय तक बनाए रख सके। इस दृष्टिकोण से परियोजना क्षेत्रों में निरंतर आय वृद्धि, सामाजिक समानता और समुदाय–आधारित ग्रामीण विकास के रास्ते बन रहे हैं। नींव रखने में सफल रहा।

महिलाओं के नेतृत्व वाली आजीविका और आर्थिक उद्यम

बीआरएलएफ समर्थित पहलों में महिलाएं महत्वपूर्ण आर्थिक अभिनेताओं के रूप में उभरी हैं, जिससे घरेलू आय बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। वे छोटे पशुधन पालन और वन उपज संग्रह से लेकर प्रमुख उत्पादक समूहों (पीजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण उद्यमों तक उत्पादन, प्रबंधन और बाजार पहुंच के केंद्र में हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 में, बीटीआर, असम ने यह सुनिश्चित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की कि सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं के नाम पर भूमि आधारित संपत्ति स्वीकृत की जाए। इस बीच, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले उत्पादक समूहों ने सामूहिक रूप से इनपुट और कृषि उपज की खरीद की, जिससे लागत में काफी कमी आई और सदस्यों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार हुआ। ओडिशा और झारखंड में, कृषि–उद्यमियों–जिनमें से कई महिलाएं हैं– ने उच्च मूल्य वाली फसलों, बागवानी और गैर–लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) में पहल का नेतृत्व किया, जो अक्सर राज्य और राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ते हैं।

इन प्रयासों ने न केवल हजारों परिवारों की आय में वृद्धि की है, बल्कि सामूहिक उद्यमों में महिलाओं के नेतृत्व को भी मजबूत किया है, उन्हें अपने समुदायों के भीतर निर्णय लेने वालों और रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

1,50,542
महिला लाभार्थियों को सहायता प्राप्त

1,67,293
लाभान्वित कुल छोटे और सीमांत किसान

70
एनटीएफपी आधारित आजीविका में महिलाओं का हिस्सा (%)

7,002
पीवीटीजी परिवारों को सहायता प्राप्त (स्थापना के बाद से)

38,726
बैकयार्ड मुर्गी पालन/बकरी/मत्स्य पालन में महिलाएं

60 करोड़+
महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों द्वारा नियंत्रित उपज का टर्नओवर/मूल्य (₹)

"मेरा नाम पुष्पांजलि महंता है, मैं धनकानाल जिले के कंकादहड़ ब्लॉक से हूँ। मैं कंकादहड़ किसान उत्पादक कंपनी की निदेशक हूँ, जिसमें 23 उत्पादक समूह और 1,500 शेयरधारक शामिल हैं। एपीसी परियोजना से पहले, हमें बाजार तक पहुँच और कम आय की समस्या थी। लेकिन समर्थन मिलने के बाद हमारी खेती बेहतर हुई और हमारी आय दोगुनी हो गई। हमने अपने गाँव में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा भी बनाई, जिसका उद्घाटन कलेक्टर ने किया। पहले मैं सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकिचाती थी, लेकिन अब मैं एक हजार से अधिक सदस्यों वाली बैठकों की आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करती हूँ। मेरा परिवार, जो पहले अनिश्चित था, अब मेरे साथ खड़ा है।"

पुष्पांजलि की यह यात्रा दिखाती है कि सही समर्थन के साथ उत्पादक कंपनियाँ ग्रामीण भारत में जीवन और नेतृत्व को कैसे बदल सकती हैं।

सामुदायिक संस्थानों में सहभागिता

मजबूत सामुदायिक संस्थाएँ महिलाओं और वंचित समूहों की आवाज को स्थानीय विकास में प्रभावी बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। बीआरएलएफ ने महिलाओं और आदिवासी परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SHG), उत्पादक समूह (PG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और अन्य जमीनी स्तर की संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान दिया है।

वित्त वर्ष 2024–25 में बीआरएलएफ के समर्थन से इन संस्थाओं में महिलाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी और नेतृत्व और गहरा हुआ। ओडिशा और झारखंड में, SHG ने कृषि और गैर–कृषि आजीविका पहलों के डिजाइन और क्रियान्वयन का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, महिलाएँ PG और FPO में नेतृत्व पदों पर चुनी गईं, जहाँ उन्होंने इनपुट खरीद, विपणन और मूल्य संवर्धन के फैसले लिए। BTR, असम में क्षमता निर्माण के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि नए बने सामुदायिक समूह स्वतंत्र, सुव्यवस्थित संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें और सरकारी विभागों तथा बाजार के पक्षकारों से संवाद कर सकें।

इन जमीनी संस्थाओं ने न केवल महिलाओं की दृश्यता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाई, बल्कि सामूहिक आर्थिक कार्रवाई और वकालत के मजबूत मंच भी बनाए, जिससे विकास की प्राथमिकताएँ सबसे वंचित लोगों की जरूरतों के अनुरूप बन सकें।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

1,37,331
पीजी/एफपीओ में महिलाएं

985
महिलाओं के नेतृत्व वाले आजीविका समूह/उद्यम (एफपीओ, पीसी, पीजी, आदि)

72
सामुदायिक संस्थानों का गठन (एसएचजी, सामूहिक)

असम के बीटीआर के नगरीजुली ब्लॉक के गोइबाड़ी गाँव में, 15 महिला किसानों ने सामूहिक खेती और जलवायु–अनुकूल प्रथाओं द्वारा अपनी आजीविका में सुधार किया है। एएसआरएलएम द्वारा प्रवर्तित सरती उत्पादक समूह के सदस्यों के रूप में, वे 6.5 एकड़ भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते हैं। कृषि विभाग से बीज सहायता और सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित डोंग (नहर) के माध्यम से पानी की पहुंच ने उनके खेतों को फलने–फूलने में मदद की है।

उनकी वर्तमान फसल में मक्का (1.5 एकड़), धान (4 एकड़), बाजरा (0.7 एकड़) और ड्रैगन फ्रूट (0.3 एकड़) शामिल हैं, जिससे 2.8 मीट्रिक टन मक्का की पैदावार होती है। समूह अब 20 एकड़ तक खेती का विस्तार करने की योजना बना रहा है, अगले सीजन में दालों को जोड़ रहा है और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक पावर टिलर का प्रस्ताव दिया है।

"एक साथ काम करने से न केवल हमारी फसल में सुधार हुआ है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बेहतर हुआ है। अब हम अपने समुदाय के लिए बड़े सपने देखते हैं," समूह के एक सदस्य के कथन।

अधिकार, मान्यता और अधिकार/हकदारी सुरक्षित करना

जमीन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित करना लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक मजबूती बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बीआरएलएफ ने इस बात पर जोर दिया है कि वंचित समुदाय न सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों, बल्कि उन्हें पाने और इस्तेमाल करने में पूरा सहयोग भी मिले।

देश के अलग–अलग इलाकों में बीआरएलएफ ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव को मजबूत किया है, जैसे – मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अन्य। इसके जरिए आदिवासी परिवारों को पेंशन, राशन कार्ड और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ मिल पाए।

इन पहलों से ग्रामीण और आदिवासी परिवारों को अपनी जमीन और संसाधनों पर अधिक सुरक्षा मिली है, सामुदायिक संस्थाओं में उनकी बातचीत और सौदेबाजी की ताकत बढ़ी है और भविष्य की बेहतर योजना बनाने की उनकी क्षमता भी मजबूत हुई है।

39 वर्षीय हितेश डेका, असम के उदालगुरी जिले के भोल्लाकाश गांव के रहने वाले हैं। उनके लिए मनरेगा के तहत एक फार्म तालाब का निर्माण उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने मनरेगा योजनाओं के बारे में टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी पाई। रुचि होने पर वे वीसीडीसी अध्यक्ष की बैठक में शामिल हुए और मनरेगा के तहत एक फार्म तालाब बनाने का अनुरोध किया।

तालाब बनने और सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद, हितेश ने एकीकृत खेती शुरू की–वे तालाब में मछली पालन करते हैं और उसके किनारों पर हल्दी, उड़द, असम नींबू और सुपारी की खेती करते हैं। पानी की उपलब्धता से अब वे आसपास की जमीन पर वैकल्पिक फसलों की योजना भी बना पा रहे हैं।

"इस तालाब ने मेरी खेती के प्रति सोच बदल दी है। अब मैंने अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ा लिए हैं। मुझे अब अपने परिवार की आजीविका को लेकर सुरक्षा महसूस होती है," वे बताते हैं।

हितेश की कहानी दिखाती है कि मनरेगा जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता और उनकी पहुंच किस तरह किसानों की मजबूती बढ़ा सकती है और उन्हें विविध व टिकाऊ आजीविका के रास्ते पर ला सकती है।

प्रमुख डेटा (वित्त वर्ष 2024–25)

7,19,533

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े परिवार (शुरुआत से)

समन्वय 2025 में भारत की अलग–अलग संस्कृतियों की झलक देखने को मिली।

बहुत से छात्रों ने मिजोरम का सुंदर चेराव नृत्य पेश किया, जिसके बाद असम के उत्साह से भरपूर बोडो और हुसोरी बिहू नृत्यकला देखने को मिली। कलामंदिर के कलाकारों ने, झारखंड सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से, शानदार पुरुलिया छाऊ, बाहा, फिरकल और पैका नृत्य दिखाकर सबका मन मोह लिया।

इस कार्यक्रम का एक बहुत ही खास आकर्षण था चारुल और विनय की अगुवाई में 'लोकनाद समूह का गीत–संगीत' इसमें दर्शकों को संगीत के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश प्रदान किए गए थे।

"हमारी कहानी, हमारी जुबानी" सत्र में भिन्न–भिन्न गाँवों से आए लोगों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए कि– कैसे निरंतर परिश्रम और सहयोग से उनके जीवन में सुधार आया और आजीविका अधिक मजबूत हुई। उन्हें उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया।

'समन्वय' का उद्देश्य था–सहयोग और साझेदारी की भावना को नई पहचान देना। इस कार्यक्रम में उन संस्थाओं, सरकारी विभागों और सहयोगी संगठनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने भारत के दूर–दराज इलाकों में लोगों की आजीविका मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किए हैं।

ये पुरस्कार ग्रामीण आजीविका को सशक्त और स्थायी बनाने में दिए गए उनके उल्लेखनीय योगदान के प्रतीक हैं।

ग्रुप फोटो

समन्वय 2025: विभिन्न स्वरों और विचारों का संगम

"समन्वय", संस्कृत के दो शब्दों – 'स' (अर्थात समान या बराबर) और 'अन्वय' (अर्थात जुड़ाव या संगम) – से मिलकर बना है। यह विविध दृष्टिकोणों और विशेषज्ञताओं के संतुलित मेल का प्रतीक है, जो सभी को एक साझा लक्ष्य की ओर सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

बीआरएलएफ और एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा सह–आयोजित इस दो दिवसीय आयोजन ने आदिवासी नेताओं, नागरिक समाज संगठनों, सरकारी प्रतिनिधियों, सीएसआर और विद्यार्थियों के उत्साही समूह को एक साथ लाकर संवाद, चिंतन, मान्यता और सबसे बढ़कर सामूहिक आशा का मंच दिया।

इन दो दिनों में प्रतिभागियों ने भारत के आदिवासी इलाकों में समावेशी और सतत आजीविकाओं के नए मार्गों पर विचार किया। पहले दिन की शुरुआत सरकार, नागरिक समाज संगठनों और कॉरपोरेट जगत के बीच इस बात पर गहन चर्चा से हुई कि कैसे मिलकर ऐसे तंत्र बनाए जा सकते हैं, जो न सिर्फ परिवर्तनकारी हों बल्कि सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हों और समुदाय की अगुवाई में आगे बढ़ें। दूसरे दिन का आयोजन आदिवासी संस्कृति के उत्सव को समर्पित रहा, जिसमें धैर्य और जिजीविषा की कहानियों का सम्मान किया गया, साझेदारी के प्रयासों को सराहा गया और उन लोगों, संस्थाओं और नवाचारों को सामने लाया गया, जो बदलाव को संभव बना रहे हैं।

श्री प्रमोद बोरो, मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम)
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, असम

"मैं बीआरएलएफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समन्वय – राष्ट्रीय जनजातीय आजीविका शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। बीटीआर में बीआरएलएफ जो काम कर रहा है वह उल्लेखनीय है। बहुत कम समय में, इसने खुद को इस क्षेत्र में अग्रणी विकास संगठन के रूप में स्थापित किया है। बीटीआर सरकार के साथ इसके सहयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी नीतियां सबसे हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों तक पहुंचें। मैं पूरी बीआरएलएफ टीम को इतने महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।"

सुश्री पी लालरिनपुई, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, मिजोरम सरकार की मंत्री

"इस विशेष अवसर पर आपके सामने खड़ा होना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है। विकास की प्रक्रिया में, दूरदराज के क्षेत्र अक्सर पीछे रह जाते हैं और यह पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष रूप से एक सच बात है। देश के कुछ हिस्सों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अनुरूप नीतियों और एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह आयोजन एक–दूसरे से सीखने, देश भर के सफल मॉडल साझा करने और जनजातीय विकास के लिए स्थायी मार्ग बनाने में उपयोगी होगा। गीतों और नृत्यों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति के उत्सव ने भी इस आयोजन में एक अनूठा आकर्षण जोड़ा है। मैं बीआरएलएफ टीम को आत्मनिर्भर जनजातीय भारत के निर्माण के अपने जनादेश को प्राप्त करने में सफलता की कामना करती हूँ।"

सुश्री ध्रुवी शाह, कार्यकारी ट्रस्टी और एक्सिस बैंक फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

बीआरएलएफ की 10 वर्षीय यात्रा में, हम पिछले पाँच वर्षों से साझीदार रहे हैं और यह वास्तव में एक अनूठा संगठन है–जो सरकार, नागरिक समाज और हमारे जैसे फंडर्स के बीच स्थित है। बीआरएलएफ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम है कि सामूहिक प्रयासों से क्या–क्या हासिल किया जा सकता है। जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों का एक साथ आना जरूरी है और यही काम बीआरएलएफ और एक्सिस बैंक फाउंडेशन कर रहे हैं। हमें यह भी आवश्यक है कि हम अपने अनुभव साझा करें ताकि फंडिंग इकोसिस्टम को सही दिशा मिल सके। कई फंडर्स इस क्षेत्र में नए हैं–जैसे, CSR की शुरुआत केवल 10 साल पहले हुई थी। इसलिए यह जरूरी है कि फंडर्स को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया जाए और साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए सामूहिक नजरिया तैयार किया जाए।"

डॉ. मिहिर शाह, मेंटर और बीआरएलएफ के संस्थापक अध्यक्ष

"अगर किसी ने मुझे 10 साल पहले बताया होता कि संगठन एक दिन इस तरह का आयोजन करेगा, तो मुझे यह अकल्पनीय लगता। बीआरएलएफ आज भारतीय विकास क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखता है – इस तरह की वास्तुकला के साथ कोई अन्य संगठन मौजूद नहीं है। जनजातीय समुदायों को एक अनूठे प्रकार के विकास की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि समन्वय एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। यहां होने वाली चर्चा और विचार–विमर्श निश्चित रूप से जनजातीय लोगों के लिए बेहतर नीति निर्माण और उनके विकास में योगदान देंगे।"

श्री कुलदीप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), बीआरएलएफ

"मैं 'समन्वय' में पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बीआरएलएफ का एक प्रमुख दायित्व जमीनी स्तर पर कार्यरत सिविल सोसायटी संगठनों, सरकार, शिक्षा–जगत, कॉरपोरेट जगत और परोपकारी संस्थाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। 'समन्वय' हमारी उसी दिशा में एक पहल है। यह आयोजन न केवल सततता और लचीलापन के नए मॉडल गढ़ने में सहायक होगा, बल्कि बीआरएलएफ और इसके साझीदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों को सही दिशा प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।"

पैनल चर्चा – विचार साझा करना, प्रेरक कार्रवाई

समन्वय 2025 के दौरान चार सार्थक पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के प्रतिनिधियों, कॉरपोरेट जगत और जमीनी स्तर की आवाजों ने मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में समावेशी और टिकाऊ आजीविकाओं के रास्ते तलाशे।

1. **समावेशी और सतत आजीविका के लिए मनरेगा की संभावनाएँ** – विशेषज्ञों ने चर्चा की कि मनरेगा को केवल मजदूरी तक सीमित न रखकर कैसे दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण और ग्रामीण बदलाव का साधन बनाया जा सकता है।

2. **विविध आजीविका रणनीतियों के उभरते मॉडल** – जलवायु–संवेदी कृषि से लेकर उद्यम विकास तक, ऐसे नवीन मॉडल प्रस्तुत किए गए जो आदिवासी समुदायों की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए और बड़े स्तर पर अपनाए जा सकते हैं।

3. **भविष्य के लिए तैयार सामुदायिक संस्थाएँ** – लचीलापन और नेतृत्व – चर्चाओं का केंद्र यह रहा कि कैसे सामुदायिक संस्थाओं को बदलते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में सक्षम, सशक्त और अग्रणी बनाया जाए।

4. **नई संगठनात्मक राहें: सहयोग से बढ़त – बीआरएलएफ का राज्य साझेदारी मॉडल** – इसमें सरकार, CSOs और अन्य साझेदारों के साथ बीआरएलएफ की सफल साझेदारियों को प्रस्तुत किया गया, जो दिखाता है कि समन्वय कैसे प्रणालीगत बदलाव ला सकता है और आदिवासी क्षेत्रों में असर को कई गुना बढ़ा सकता है।

इन संवादों ने ठोस सीख, आपसी आदान–प्रदान और ग्रामीण भविष्य को मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया।

क्षमता निर्माण

बीआरएलएफ का क्षमता निर्माण (Capacity-Building) विभाग का उद्देश्य उन संस्थाओं और पेशेवरों की क्षमता को मजबूत करना है, जो भारत के आदिवासी इलाकों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीआरएलएफ के ये कार्यक्रम नागरिक समाज संगठन (CSOs), सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs), पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs), सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा, SRLM, TWD, ITDA) को लागू करने वाले जमीनी स्तर के कार्मिक और ग्रामीण विकास से जुड़े पेशेवरों की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

बीआरएलएफ का शिक्षण कार्यक्रम पोर्टफोलियो विशेष हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है:

1. तकनीकी क्षमताओं के अंतर्गत ग्रामीण पेशेवरों के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मिट्टी और जल संरक्षण, Participatory Ground Water Management (PGWM), सतत खेती और कृषि व गैर–कृषि आजीविका पहलों में दक्षता।
2. संस्थागत क्षमताओं के अंतर्गत CSOs और CBOs के लिए सुशासन, संस्थान निर्माण, व्यवसाय योजना एवं विकास, मॉनिटरिंग–इवैल्यूएशन–लर्निंग (MEL), वित्तीय प्रबंधन और अनुपालन, संगठनात्मक उत्कृष्टता और विकास।
3. नेतृत्व क्षमताएँ – CBO सदस्यों, PRI प्रतिनिधियों, जमीनी स्तर के कार्मिकों और सामुदायिक नेताओं के लिए, ताकि वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को संस्थानों और समुदायों में पिरो सकें।

प्रमुख डेटा

2662

बीआरएलएफ सीबी पहल के माध्यम से संरचित प्रशिक्षण/शिक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले पेशेवरों की संख्या (मार्च 2025 तक संचयी/कुल)

391

2024–25 में बीआरएलएफ की संरचित प्रशिक्षण/शिक्षा पहल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पेशेवरों की संख्या

शैक्षणिक संस्थानों के साथ बीआरएलएफ साझेदारियाँ

ग्रामीण विकास क्षेत्र के सामने कई जटिल चुनौतियाँ हैं–विकास और समानता का संतुलन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, तथा गरीब और कमजोर समुदायों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसे परिदृश्य ने सरकारी और गैर–सरकारी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर यह स्पष्ट किया है कि आज ऐसे पहलों की आवश्यकता है जो चिंतनशील हों, मजबूत रूप से तैयार किए गए हों और नवोन्मेषी व अनुकूलनशील दृष्टिकोण से लागू किए जा सकें। इस लक्ष्य को संभव बनाने के लिए यह मान्यता बढ़ रही है कि ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्यरत और भावी पेशेवरों की क्षमता–विकास संबंधी चुनौतियों को गंभीरता से संबोधित करना आवश्यक है–चाहे वे सिविल सोसाइटी संगठन (सीएसओ), शासकीय संस्थान, पंचायती राज संस्थाएँ या क्लस्टर स्तरीय महासंघ के निर्वाचित प्रतिनिधि क्यों न हों। इसी दिशा में बीआरएलएफ शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी करता है, ताकि विश्वविद्यालय आधारित शिक्षण कार्यक्रमों का सह–निर्माण किया जा सके जो संदर्भानुकूल हों और शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत भी। ये साझेदारी कार्यक्रम, बीआरएलएफ और संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित होते हैं और विशेषकर युवाओं, खासकर आदिवासी पेशेवरों के लिए अनूठे अवसर प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी वह आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं जो उन्हें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास पहलों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाते हैं। इन विश्वविद्यालय साझेदारी कार्यक्रमों में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः क्षेत्रीय अनुभव आधारित होती है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को न केवल गहरी समझ प्रदान करना है,

बल्कि उन्हें ऐसे कौशल से भी सुसज्जित करना है जो जमीनी स्तर पर प्रभावकारी और सकारात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक गति और स्थायित्व उत्पन्न कर सके। इन कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम व्यापक है और इसमें विशेष रूप से लोगों के अनुभवजन्य ज्ञान का सम्मान किया गया है। साथ ही, इन्हें नवीनतम व्यवहारिक उपकरणों और पद्धतियों के साथ जोड़ा गया है, ताकि प्रतिभागी अपने कार्यक्षेत्र में वास्तविक बदलाव ला सकें।

विकास प्रबंधन में एमबीए:

वित्त वर्ष 2024–25 में, बीआरएलएफ और आईआईएचएमआर साझेदारी प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों के पूरा होने के साथ संपन्न हुई। 2017 और 2024 के बीच, विकास प्रबंधन कार्यक्रम में एमबीए ने कुल 39 युवा पेशेवरों को स्नातक किया। विकास प्रबंधन में एमबीए आईआईएचएमआरयू, जयपुर द्वारा पेश किया जाने वाला सीएसआर और ईएसजी प्रबंधन या सूक्ष्म और लघु व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ एक अद्वितीय दो साल, पूर्णकालिक एमबीए प्रोग्राम था। पाठ्यक्रम, अपने फोकस में अलग, शिक्षार्थियों को सीएसओ, सीएसआर पहल और छोटे व्यवसायों के प्रबंधन में कौशल से लैस करता है। इसने शिक्षार्थियों को सरकारी कल्याणकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रबंधन सिद्धांतों और कौशल की भूमिका सीखने का अवसर भी प्रदान किया, जो इसे अन्य एमबीए कार्यक्रमों से अलग करता है। एमबीए–डीएम प्रोग्राम पूरा करने वाले 39 छात्र अब देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

ग्रामीण प्रबंधन में एमए:

शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (एसएनआइओई) में ग्रामीण प्रबंधन में एमए कार्यक्रम का उद्देश्य नवोन्मेषी और रचनात्मक नेतृत्वकर्ताओं की नई पीढ़ी को तैयार करना है, ताकि वे ग्रामीण भारत में उभरती चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए आवश्यक समझ और कौशल विकसित कर सकें। सन् 2022 में आरंभ होने के बाद से एसएनआइओई ने बीआरएलएफ के सहयोग से 29 छात्रवृत्तियाँ युवा आदिवासी पेशेवरों को प्रदान की हैं। इन छात्रवृत्तियों के अंतर्गत मध्य भारत के आदिवासी और कमजोर भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। ये छात्रवृत्तियाँ योग्य विद्यार्थियों को उच्च प्रतिष्ठा और शैक्षणिक गुणवत्ता वाले संस्थान में ग्रामीण प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे वे अपने समुदायों और व्यापक ग्रामीण भारत में सार्थक बदलाव ला सकें।

ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फैलोशिप प्रोग्राम

ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया (जीएचसीआई) परियोजना 2021 में ग्रामीण और आदिवासी युवाओं का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी, शुरुआत में चार राज्यों: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में। 2024 तक, इसका विस्तार 8 राज्यों: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में हो गया। ग्रीन हब फेलोशिप भोपाल में स्थित 10 महीने की आवासीय फेलोशिप है। मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के 25 युवाओं का चयन किया जाता है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण और स्थायी आजीविका पर ध्यान देने के साथ वीडियो स्टोरीटेलिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। वीडियो का उपयोग इस क्षेत्र में उन्हें संलग्न करने और सशक्त बनाने के लिए परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जहां वे पारिस्थितिक सुरक्षा को भविष्य की नींव के रूप में देखना शुरू करते हैं। अपने अंतिम वर्ष में, ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया के पास 82 फेलो का एक नेटवर्क है, जो 53 जिलों से 24 जनजातियों (एससी, ओबीसी और सामान्य श्रेणियों के अलावा) का प्रतिनिधित्व करता है। इस फेलोशिप ने अपने पहले चार वर्षों में 52 संगठनों के साथ भागीदारी की है।

संगठनों के साथ साझेदारी में 48 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रामीण आजीविका, स्थायी कृषि पद्धतियों, वन्यजीव संरक्षण, लैंगिक न्याय, शिक्षा, युवा विकास, गैर–कीटनाशक प्रबंधन, वाटरशेड विकास और स्वदेशी ज्ञान जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया है।

फेलोशिप का समापन ग्रीन हब फेस्टिवल में होता है, जहां फेलो फिल्में दिखाते हैं। इस महोत्सव में साझेदार संगठनों, नागरिक समाज, सरकारी प्रतिनिधियों, चिकित्सकों, फिल्म निर्माताओं और छात्रों की भागीदारी देखी जाती है। यहां दो दिनों में प्रतिदिन लगभग 300–400 लोग आते हैं।

ग्रीन हब की पुरस्कार विजेता फिल्में

- ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया की सुनील कुमावत और हरि कुजाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म, "बीज बैंक –परंपरागत एन किसनो के संग" को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड 2023 मिला।
- कलायानी नाइक की फिल्म प्रस्ताव, "को–एग्जिस्टेन्स विथ क्रोकोडाइल्स (मगरमच्छों के साथ सह–अस्तित्व)" को 2024 में ग्रीन स्टोरीज के पहले संस्करण के लिए चुना गया था।

वाटरशेड प्रबंधन पर डिजिटाइज्ड मॉड्यूल

(https://www-chvkj.y.Q-in/e&learning/)

वित्त वर्ष 2024–25 में बीआरएलएफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए वॉटरशेड प्रबंधन पर एक डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया। इस मॉड्यूल की सामग्री बीआरएलएफ के सीपीआरएल कार्यक्रम के लिए पहले से संकलित संसाधनों को रूपांतरित करके विकसित की गई है। यह कोर्स अब पेशेवरों और इच्छुक प्रतिभागियों के लिए बीआरएलएफ लर्निंग पोर्टल पर उपलब्ध है।

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन

बीआरएलएफ का अनुसन्धान और एमईएल (MEL) विभाग भारत के आदिवासी समुदायों की ग्रामीण आजीविकाओं पर साक्ष्य–आधारित ज्ञान तैयार करने के लिए कार्य करता है। इसके तहत बीआरएलएफ की राज्य स्तरीय इकाइयों, सरकार, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर मौलिक अनुसन्धान और ज्ञान–संक्षेप (Knowledge Briefs) तैयार किए जाते हैं, जिनमें नीतियों और वर्तमान प्रथाओं से जुड़े कारगर सुझाव और लर्निंग सम्मिलित होती हैं, विशेषकर ग्रामीण आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में।

अनुसन्धान और ज्ञान प्रबंधन विभाग द्वारा संकलित और सह–निर्मित किए गए संसाधन मुख्य रूप से इन उद्देश्यों के लिए हैं –

- बीआरएलएफ और उसके साझेदारों के लिए एक गतिशील लर्निंग ईकोसिस्टम उपलब्ध कराना
- अभ्यास–आधारित लर्निंग को केंद्र और राज्य स्तर की नीतियों में शामिल करना
- प्रमुख हितधारकों के बीच ज्ञान विनिमय और सह–निर्माण को प्रोत्साहित करना
- एक साझा ज्ञान अवसंरचना का निर्माण करना, जिससे भारत के आदिवासी इलाकों में ग्रामीण आजीविकाएँ और मजबूत हों

वित्त वर्ष 2024–25 में बीआरएलएफ ने ऐसे कई ज्ञान दस्तावेज और सामग्री तैयार किए, जिन्होंने न केवल कार्यक्रम–क्रियान्वयन में सुधार किया बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीतिनिर्माण की दिशा को भी प्रभावित किया।

चार राज्यों में बीआरएलएफ कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन

बीआरएलएफ की कार्यक्रमगत पहलों का स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन (Independent Impact Evaluation) वर्ष 2017 से 2024 के बीच किया जा रहा है। यह पहल बीआरएलएफ के अनुसन्धान विभाग द्वारा एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की भागीदारी से शुरू की गई थी। मूल्यांकन का कार्य बीआरएलएफ के चार राज्यों—झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल—में किया जा रहा है, जहाँ 2017 से हस्तक्षेप चल रहे हैं।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं:

- यह आकलन करना कि बीआरएलएफ के हस्तक्षेप कितने प्रभावी रहे हैं और क्या उन्होंने अपने शुरुआती लक्ष्यों—जैसे सतत आय सुनिश्चित करना, जलवायु अनुकूलता, संरक्षण और जैव–विविधता में वृद्धि, प्रभावी शासन, प्रमुख हितधारकों की व्यक्तिगत व संस्थागत क्षमताओं का विकास और आदिवासी व कमजोर वर्गों के अधिकारों व हकदारी की मान्यता—को हासिल किया है।
- यह देखना कि राज्य स्तरीय साझेदारी परियोजनाएँ किस हद तक लैंगिक समानता (Gender Mainstreaming) को एक अभिन्न रणनीति के रूप में लागू कर पाई हैं।
- बीआरएलएफ के सहयोगी मॉडल की संस्थागत संरचना का दस्तावेजीकरण और उसका आकलन करना—उसकी प्रासंगिकता और जमीनी स्तर पर उसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- तेज सीख और सुझाव तैयार करना ताकि बीआरएलएफ के कार्यक्रम डिजाइन, सहयोगी क्रियान्वयन रणनीति और प्रदर्शन मानकों को और बेहतर बनाया जा सके।
- आजीविका संबंधी पहलों से अच्छी प्रथाओं, सफल मॉडल, प्रमुख चुनौतियों और सीख को प्रत्यक्ष व तुलनात्मक साक्ष्यों के साथ दर्ज करना।

यह अध्ययन बीआरएलएफ की विभिन्न पहलों के कुल प्रभाव का आकलन करेगा। मुख्य रूप से इसमें महिला किसानों की भूमिका और नेतृत्व में हुई वृद्धि, स्थानीय संस्थाओं की क्षमता को मजबूत बनाने के काम और पर्यावरण के संतुलन तथा संरक्षण को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में इस स्वतंत्र जाँच के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया चल रही है।

विश्लेषणात्मक केस स्टडीज निर्माण

विश्लेषणात्मक केस स्टडीज क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों और अभ्यासकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सीखने का माध्यम हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बीआरएलएफ के अनुसन्धान विभाग ने मनरेगा योजना और क्रियान्वयन, कृषि उत्पादन क्लस्टर्स, और सतत आजीविका मॉडलों पर विश्लेषणात्मक केस स्टडीज तैयार किए हैं, जो बीआरएलएफ और उसके साझेदारों के फील्ड अनुभवों पर आधारित थीं। इस वर्ष झारखंड से मनरेगा की सहभागी योजना और क्रियान्वयन पर केस स्टडी पूरी की गई।

प्रैक्टिस सपोर्ट नोट्स (PSNs) का निर्माण जारी है, जिनमें तीन के ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं और चौथे (एपीसी पर) को पुनः लिखा जा रहा है। इम्पैक्ट मूल्यांकन अध्ययन की आंतरिक रिपोर्ट अक्टूबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। बीआरएलएफ राष्ट्रीय अनुकूलन योजना 2035 के 'गरीबी उन्मूलन और आजीविका' अध्याय पर कार्यरत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने द्वितीयक शोध और अध्याय संरचना को मंजूरी दे दी है। इसका पहला ड्राफ्ट और हितधारक परामर्श अप्रैल 2025 तक पूरा होने वाले हैं। बीआरएलएफ को मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन पर नीति पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, जिसे GIZ और PRADAN के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, बीआरएलएफ ने आईआईटी दिल्ली और RR। नेटवर्क के साझेदारी में फार्म पोंड पर सहयोगी शोध शुरू किया।

जीवि–दाः–हसा, झारखंड से केस स्टडीज

विश्लेषणात्मक केस स्टडीज भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) की यात्रा को ट्रेस करती हैं, जो मनरेगा सेल के साथ साझेदारी में स्थापित राज्य–स्तरीय संघ के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की संभावनाओं को नए सिरे से देखती हैं। इनका उद्देश्य बढ़ती असमानताओं, संभावित जलवायु जोखिमों और बहु–हितधारक समन्वय पहलों में प्रभावी शासन की चुनौतियों को समझना है।

जीवि दाः हसा प्रोग्राम झारखंड सरकार और बीआरएलएफ की संयुक्त पहल है, जो राज्य के 24 ब्लॉक में आदिवासी समुदायों के जीवन और आजीविका सुधारने के लिए प्रमुख सरकारी विभागों, 12 नागरिक समाज संगठनों और चार वित्तीय संस्थाओं को एक मंच पर लाता है। ये केस स्टडीज उन प्रमुख हितधारकों के अनुभवों को एकत्र करती हैं, जिन्होंने बीआरएलएफ के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (SPMU) के नेतृत्व में एक चुस्त संस्थागत ढांचे और हस्तक्षेप रणनीतियों का निर्माण किया, जो समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तीन स्तंभ—समानता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था—को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं।

इन केस स्टडीज में SPMU संचालकों, बीआरएलएफ के साझेदार CSO के सदस्यों और उन समुदायिक सदस्यों की आवाज शामिल है, जो मनरेगास के माध्यम से तकनीक–सक्षम सहभागी वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग करके NRM और आजीविका संपत्ति बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रयास, ऊर्जा, जोश, सहयोगी भावना और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता को सामने लाता है, जो इस तरह की बड़ी पहल को एक साथ रखने में मदद करती है।

जीवि दाः हसा प्रोग्राम में नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिला मेट्स के साथ व्यापक काम के माध्यम से, यह पहल मनरेगा की संभावनाओं को भी बढ़ाना चाहती है—एक ऐसा अधिनियम जो समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है—और इसे लैंगिक संबंधों, साथ ही जेंडर और भूमि, जल और शासन संस्थाओं के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक मंच के रूप में प्रस्तुत करती है।

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में DWIMU परियोजना के लिए बेसलाइन

वित्त वर्ष 2024–25 में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) में थर्ड–पार्टी बेसलाइन सर्वे पूरा किया गया, जिसमें लगभग 1250 घरों को शामिल किया गया। DWIMU प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस क्षेत्र में समग्र आजीविका विकास सुनिश्चित करना है और यह ग्राम परिषद विकास समितियों (VCDCs) तथा स्थानीय समुदाय–आधारित संगठनों की क्षमता निर्माण गतिविधियों में संलग्न है। यह परियोजना बोडोलैंड की कमजोर और संवेदनशील समुदायों के जीवन और आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती है।

प्रोजेक्ट वर्तमान में तीन जिलों (उड़ालगुड़ी, तमुलपुर और बकसा) के सात ब्लॉक्स (माजबट, उड़ालगुड़ी, तमुलपुर, नाग्रिजुली, गोरेस्वर, बकसा और धामधामा) में लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य पाँच वर्षों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलना और उनके सतत विकास में योगदान देना है।

DWIMU प्रोजेक्ट की बेसलाइन रिपोर्ट कार्यक्रम टीम को मैदान से प्राप्त नए चुनौतियों के अनुसार प्रमुख हस्तक्षेपों की योजना और डिजाइन तैयार करने का अवसर देती है। इसके साथ ही यह अगले चार वर्षों में परियोजना की प्रगति को ट्रैक करने का भी एक उपकरण बनेगी।

ग्रीन कॉलेज ओडिशा के लिए बेसलाइन की शुरुआत

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर (APC) 2.0 प्रोग्राम, जो कि भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन और ओडिशा सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है, का उद्देश्य राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सतत आजीविका पहलों को बढ़ाना है। इस प्रोग्राम का फोकस खेती से जुड़े संसाधनों को मजबूत करने, मूल्य शृंखलाओं (Value Chains) को सशक्त बनाने और आजीविका के विकल्पों को विविध बनाने पर है, जिसमें विशेष रूप से महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। APC 2.0 का लक्ष्य प्रत्येक ब्लॉक में 5,000 से अधिक किसानों तक पहुँच बनाना है, ताकि उनकी आय बढ़े, उनका जीवन अधिक सुरक्षित और लचीला बने और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित हो। इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने के लिए Green College पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य APC 2.0 में क्षमता निर्माण के घटकों को मजबूत करना है।

इस समय की बेसलाइन स्टडी को एक डायग्नोस्टिक अभ्यास के रूप में तैयार किया गया है, ताकि Green College पहलों के तहत वर्तमान क्षमता, प्रथाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थिति का आकलन किया जा सके। इस अध्ययन से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति अपेक्षित हैरू

1. ग्रीन कॉलेज मॉनिटरिंग के लिए पहचाने गए लगभग 60 संकेतकों के लिए मानक मूल्य निर्धारित करना।
2. किसानों और सामूहिक संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रणाली, संस्थागत तत्परता और प्रथाओं को अपनाने की स्थिति का मूल्यांकन करना।
3. शासन, कौशल विकास, डिजिटल तत्परता और उद्यमिता में क्षमता की खामियों की पहचान करना।
4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने, सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय बढ़ाने और इकोप्रेन्योरशिप के विस्तार के लिए मार्ग तैयार करने के लिए साक्ष्य जुटाना।

यह बेसलाइन आगे के मिडलाइन और एंडलाइन मूल्यांकन के साथ तुलना का आधार भी प्रदान करेगी, जिससे प्रोग्राम के परिणामों को व्यवस्थित रूप से मापा जा सकेगा।

राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (National Adaptation Plan) का "गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन" अध्याय

भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, ताकि गहराई से जड़ी कमजोरियों का समाधान किया जा सके और भारत की विविध भौगोलिक, जलवायु और सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में स्थानीय नेतृत्व वाले अनुकूलन प्रयासों को मजबूत करने के लिए समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ रणनीतियाँ तैयार की जा सकें।

इस संदर्भ में, गरीबी निवारण और आजीविका पर आधारित थीमैटिक वर्किंग ग्रुप (TWG) एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह समूह राष्ट्रीय अनुकूलन योजना के लिए रणनीतिक मार्ग तैयार करता है, जो व्यक्तिगत परिवारों और समुदायिक संस्थाओं के स्तर पर जमीन से ऊपर उठते हुए लचीलापन (resilience) बढ़ाने पर केंद्रित है। TWG का कार्य केवल गरीबी निवारण तक सीमित नहीं है, बल्कि टिकाऊ और जलवायु–सहिष्णु ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाएँ बनाने तक फैला है।

गरीबी निवारण और आजीविका के इस सेक्टोरल अध्याय को BRLF की शोध टीम और NIRD&PR के सहयोगियों ने सह–लेखक के रूप में तैयार किया है, जिसका नेतृत्व श्रीमती स्मृति सरन, JS (R&IL), ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रही हैं। इस अध्याय की सामग्री में थीमैटिक वर्किंग ग्रुप, एडैप्टेशन सेल, MoEF–CC, और समुदाय प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों, सरकारी प्रतिनिधियों, शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं।

सम्मेलनों और गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारीः

अनुसन्धान टीम ने इस वर्ष 11 से अधिक मंचों और सम्मेलनों में बीआरएलएफ के काम को प्रस्तुत किया, जिसमें कॉमन्स कॉन्विनिंग 2024 और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 शामिल हैं।

समन्वय 2025 पैनल चर्चाः

अनुसंधान दल ने चार विषयगत डोमेन पर साझा अभ्यास संसाधन विकसित करने के लिए समन्वय 2025 पैनल चर्चाओं का आयोजन और एंकरिंग कीः भूमि आधारित योजना और मनरेगा का कार्यान्वयन, कृषि उत्पादन क्लस्टर, स्थायी आजीविका के उभरते प्रोटोटाइप के रूप में एकीकृत कृषि प्रणाली और राज्य और नागरिक समाज की भागीदारी के सहयोगी मॉडल। चार विषयगत क्षेत्रों में हुई चर्चाओं ने आगामी वर्ष, 2025–26 के लिए बीआरएलएफ अनुसंधान टीम के अनुसंधान एजेंडे को सूचित किया है।

निगरानी, मूल्यांकन और सीख (मोनिटरिंग, इवेल्यूएशन व लर्निंग)

बीआरएलएफ में निगरानी, मूल्यांकन और सीख की प्रक्रियाएँ, संरचनाएँ और प्रणालियाँ इस तरह डिजाइन की गई हैं कि ये डेटा–आधारित निर्णय लेने में मदद करें और परियोजनाओं की बेहतर योजना और परिणाम सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बीआरएलएफ ने ऐसे प्रमुख ढांचे तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की, जो लचीले और प्रभावी कार्यक्रम संचालन को संभव बनाते हैं।

एक समग्र एमईएल फ्रेमवर्क

इस वर्ष, निगरानी, मूल्यांकन और सीख (MEL) ढांचा संगठनात्मक परिवर्तन सिद्धांत (Theory of Change) और क्रियाशीलता सिद्धांत (Theory of Action) को एक साथ लाने का काम कर रहा है। पिछले दस वर्षों में, हमारे क्रियाशीलता सिद्धांत (कार्यक्रमगत संरचना और बेहतर परिणामों के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन) और परिवर्तन सिद्धांत (संगठन का दृष्टिकोण, मिशन, दृष्टिकोण और मान्यताएँ) के बीच अंतर को पाटने के प्रयास किए गए हैं। वर्तमान MEL ढांचा BRLF की प्रमुख विषयगत गतिविधियों को एक साथ लाता है, जिनमें शामिल हैं:

1. एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
2. विविध और सतत आजीविका रणनीतियाँ
3. प्रमाणित आजीविका मॉडल के माध्यम से उद्यमिता विकास
4. सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण (FPOs – PG/PC)
5. प्रमुख हितधारकों की क्षमता निर्माण
6. सामुदायिक वन अधिकार और प्रबंधन
7. प्रमुख सरकारी योजनाओं से जुड़े अधिकार और लाभ
8. ग्रामीण आजीविका पहलों में लिंग मुख्यधारा

MEL टीम वर्तमान ढांचे में जलवायु अनुकूलन और स्थिरता संकेतकों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। यह विकसित ढांचा इस विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का आधार है, जिसमें MIS के डिजाइन और विकास भी शामिल हैं।

BRLF की विशिष्ट विषयगत गतिविधियों के लिए मानकीकृत डेटा इनपुट और रिपोर्टिंग टेम्पलेट बनाए गए हैं। ये टेम्पलेट 70: मानकीकरण और 30: भौगोलिक–सामाजिक संदर्भ के लिए अनुकूलन की सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि BRLF जिन विभिन्न सामाजिक–पर्यावरणीय क्षेत्रों में काम कर रहा है, उनके अनुरूप इस्तेमाल किया जा सके।

अत्याधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआईएस (MIS)

बीआरएलएफ की MIS (प्रबंधन सूचना प्रणाली) संरचना को नए सिरे से तैयार किया गया है ताकि फील्ड से डेटा एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के माध्यम से बीआरएलएफ सर्वे एप्लिकेशन के जरिए कैप्चर किया जा सके। प्राप्त डेटा वास्तविक समय में वेब–आधारित डै प्लेटफॉर्म के साथ सिंक हो जाता है, जिसमें प्रत्येक घराने को एक अद्वितीय पहचान कोड मिलता है और विभिन्न परियोजनाओं व हस्तक्षेपों में पूरे समय उसकी निगरानी की जाती है। MIS सिस्टम में डर–सक्षम कई चेक के माध्यम से वर्कफ्लो और सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से डेटा त्रुटियाँ काफी हद तक कम हो गई हैं और MIS तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्मियों का बोझ भी कम हुआ है। बीआरएलएफ ऐप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे नेटवर्क सीमित क्षेत्रों में भी बेहतर कार्यक्षमता मिलती है।

अब बीआरएलएफ MIS में एक गतिशील सार्वजनिक डैशबोर्ड भी है, जिसे सभी इच्छुक हितधारक देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य–स्तरीय MIS प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता–विशिष्ट डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में शामिल हितधारक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मापदंडों की निगरानी कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, MEL टीम ने बीआरएलएफ में सीखने और निगरानी के ढांचे को मजबूत करने में निम्नलिखित प्रगति की:

एक एमआईएस, एक डेटाबेस

बीआरएलएफ का MIS अब एक ही डेटाबेस में तैयार किया गया है, जिससे प्रमुख काम और परिणामों का आकलन करना आसान हो गया है और इसे अलग–अलग सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सकता है। राज्यों और टीमों में डै- और डेटाबेस को जोड़ने से डेटा का सहज प्रवाह होता है और रियल टाइम में अपडेट होने वाली कस्टम रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनते हैं। ये रिपोर्ट और डैशबोर्ड टीमों को विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपने काम की योजना बनाने और फैसले लेने में मदद करते हैं।

सभी प्रतिभागियों के लिए चरणबद्ध बेसलाइनः

अब सभी राज्यों की टीमें चरणबद्ध बेसलाइन अपनाती हैं, यानी पूरे प्रोजेक्ट में शामिल लोगों का डेटा क्रमिक रूप से एकत्र किया जाता है। इससे टीमों को लगातार काम का जायजा लेने और प्रोजेक्ट में किसी भी कमी या समस्या को जल्दी सुधारने में मदद मिलती है।

GIS आधारित योजना और क्रियान्वयनः

MEL सिस्टम में GIS का इस्तेमाल करके अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और भी सटीक और आसान हो गया है। इससे टीम को यह देखने में मदद मिलती है कि कौन–सी जगह पर काम हो रहा है, संसाधनों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और निर्णय लेने में आसानी होती है।

बीआरएलएफ में राजभाषा प्रोत्साहन पहल

राजभाषा अधिनियम, 1963, और राजभाषा पर भारतीय संसदीय समिति द्वारा निर्धारित नीतिगत ढाँचे के अनुसार, बीआरएलएफ में एक सक्रिय हिंदी राजभाषा विभाग है। यह विभाग सुनिश्चित करता है कि संगठन के भीतर राजभाषा नीतियों का पालन किया जाए।

एक समर्पित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है, जो प्रगति का आकलन करने और आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग और प्रचार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए त्रैमासिक बैठक आयोजित करती है। सभी कार्यालय पत्राचार भारत के भाषाई क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यालय आदेश, अनुबंध, समझौते और आवश्यक दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग और संसदीय समिति को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रस्तुत की जाती है।

हिंदी के व्यावहारिक और तकनीकी उपयोग को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इनमें गृह मंत्रालय द्वारा विकसित 'कंठस्थ' अनुवाद सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का प्रशिक्षण शामिल है। कार्यशालाओं में हिंदी के इतिहास और महत्व जैसे आकर्षक विषयों के साथ–साथ हिंदी पुस्तक पढ़ने के सत्र भी शामिल किए गए हैं।

हिंदी पखवाड़े के तहत रचनात्मक प्रतियोगिताओं के पखवाड़े के साथ–साथ बीआरएलएफ में हिंदी दिवस (14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला) बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से और स्वेच्छा से भाग लिया। विजेताओं को प्रमाण पत्र, प्रोत्साहन पुरस्कार राशि और उल्लेखनीय हिंदी पुस्तकों से सम्मानित किया गया।

हिंदी के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई रचनात्मक पहल शुरू की गई हैं। ऐसी ही एक पहल कर्मचारियों को अपने आधिकारिक ईमेल खातों के माध्यम से प्रतिदिन एक हिंदी उद्धरण लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें प्रविष्टियां नियमित रूप से प्रलेखित होती हैं। बीआरएलएफ संचार विभाग कर्मियों द्वारा प्रस्तुत 'किस्सा करोड़ों का' (ए टेल ऑफ मिलियन्स) नामक एक हास्य हिंदी नाटक का भी मंचन किया गया। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, एक छोटा सा हिंदी पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जिसमे हिंदी साहित्य, प्रेरक लेखन और समकालीन सामाजिक मुद्दों पर पुस्तकों का संकलन किया गया है।

इन संगठित प्रयासों के माध्यम से बीआरएलएफ का राजभाषा विभाग संगठन में हिंदी भाषा को रचनात्मकता, संवाद और प्रशासन का सशक्त और प्रभावशाली माध्यम बनाने के लिए निरंतर अग्रसर है।

रणनीतिक साझेदारी और संसाधन संग्रहण 2024 – 2025

वित्तीय वर्ष 2024–25 में बीआरएलएफ ने दीर्घकालिक संस्थागत संबंधों पर आधारित विविध रणनीति के माध्यम से अपनी संसाधन–संग्रहण और साझेदारी प्रयासों को और सुदृढ़ किया। पिछले वर्षों की गति को आगे बढ़ाते हुए, टीम ने प्रमुख सीएसआर दाताओं, बहुपक्षीय एजेंसियों और परोपकारी संस्थानों के साथ सहभागिता को गहराई देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। भारत में आयोजित प्रमुख सीएसआर आयोजनों और सम्मेलनों में भागीदारी से बीआरएलएफ की पहचान और दाता संबंध और अधिक मजबूत हुए।

इस वर्ष कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ सामने आई–जिनमें नए बहुवर्षीय अनुदान, दीर्घकालिक सीएसआर साझेदारों से नवीनीकरण और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी परियोजनाओं के लिए बढ़ता सहयोग शामिल है। बीआरएलएफ ने कुल ₹95.96 करोड़ के वित्तीय संकल्प सुरक्षित किए, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफलता के पीछे वेल्टहंगरहिल्फे (WHH), कमिंस इंडिया, एचडीएफसी बैंक परिवर्तन, जीआईजेड और ओक फाउंडेशन–स्विस फिलांथ्रॉपी फाउंडेशन जैसे नए सहयोगी थे—जिससे बीआरएलएफ के मिशन और क्रियान्वयन क्षमता में बढ़ते विश्वास का परिचय मिलता है।

दीर्घकालिक साझेदार जैसे फोर्ड फाउंडेशन, एक्सिस बैंक फाउंडेशन और यूएनडीपी ने भी अपनी सहभागिता को और गहराई दी। यह उल्लेखनीय है कि यूएनडीपी ने बीआरएलएफ के साथ राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) अध्याय पर काम किया। यह पहल केवल परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु से जुड़े मुद्दों पर बीआरएलएफ की भूमिका को भी मजबूत करती है।

बीआरएलएफ ने रणनीतिक रूप से प्रमुख संसाधन–संग्रहण और नेटवर्किंग मंचों—जैसे CSRBox, इंडिया फंडरेजिंग कॉन्फ्रेंस (IFRC), CII, MoEFCC, द नज इंस्टीट्यूट, प्लेनेट डायलॉग, ISDM और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट—में अपनी भागीदारी दर्ज की, जिससे संगठन एक विश्वसनीय क्रियान्वयन सहयोगी और बहु–हितधारक समन्वय के लिए सक्षम साझेदार के रूप में स्थापित हुआ।

इस वर्ष से एक प्रमुख सीख यह रही कि संसाधन–संग्रहण को समग्र दृष्टिकोण से अपनाना आवश्यक है—केवल वित्त जुटाने से नहीं, बल्कि बीआरएलएफ को अधिक "सुगम्य" और इस प्रकार "वित्त–योग्य" बनाना भी उतना ही आवश्यक है। आगे बीआरएलएफ अपनी पहचान और पहुँच बढ़ाने के लिए संचार, ब्रांडिंग और प्रचार पर ध्यान देगा। टीम नए तरीकों जैसे मिश्रित वित्त, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, पेरोल गिविंग और साझी फंडिंग की संभावनाएँ भी देखेगी। केवल परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के बजाय, संस्था लंबे समय तक टिकाऊ बने रहने के लिए एक स्थायी कोष (एंडोमेंट फंड) बनाने पर भी जोर देगी। साथ ही, उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों (HNIs) और परिवार फाउंडेशनों से सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सभी काम बीआरएलएफ की कार्यक्रम और राज्य–स्तरीय टीमों के साथ मिलकर किए जाएँगे ताकि क्षेत्रीय साझेदारियों के जरिए नए वित्तीय अवसर मिलें और असर अधिक गहरा हो।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार 100 करोड़ रुपये के लक्ष्य हेतु संसाधन संग्रहण विवरण

स्रोत	प्रतिबद्ध / स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2025 तक प्राप्त (करोड़ रुपये में)	2024–25 में प्राप्त हुआ (करोड़ रुपये में)
ए. एंडोमेंट फंड			
टाटा ट्रस्ट (कॉर्पस)	10.00	10.00	0
फोर्ड फाउंडेशन (कॉर्पस)	9.96	9.96	0
कुल (ए)	**19.96**	**19.96**	**0**

स्रोत	प्रतिबद्ध / स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2025 तक प्राप्त (करोड़ रुपये में)	2024–25 में प्राप्त हुआ (करोड़ रुपये में)
बी. बीआरएलएफ द्वारा प्राप्त अनुदान / दान			
यूएनडीपी और निजी दाता (अनुदान)	1.00	1.00	0
अर्घ्यम अनुदान (सहभागी भूजल प्रबंधन)	0.93	0.93	0
अर्घ्यम अनुदान (स्प्रिंगशेड परियोजना)	0.36	0.36	0
अर्घ्यम अनुदान (क्षमता निर्माण)	0.24	0.24	0
वीएटेक वैबैग ग्रांट	2.49	2.49	0
यूरोपीय संघ अनुदान	7.57	7.57	0
फोर्ड फाउंडेशन ग्रांट (ओडिशा)	4.54	4.54	0
फोर्ड फाउंडेशन ग्रांट (छत्तीसगढ़)	6.65	6.65	0
एक्सिस बैंक फाउंडेशन ग्रांट (छत्तीसगढ़)	11.25	11.25	0
एक्सिस बैंक फाउंडेशन ग्रांट (छत्तीसगढ़) – चरण II	14.75	14.75	4.06
एक्सिस बैंक फाउंडेशन ग्रांट (छत्तीसगढ़) – चरण III	54.5	4.33	4.33
एबीएफ ग्रांट (एमएच)	26.0	7.17	3.69
झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी अनुदान	0.1	0.1	0
क्राउड फंडिंग	0.05	0.05	0
महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग	1.96	1.96	0.20
हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन	3.07	3.07	0
जनजातीय कार्य मंत्रालय (योजनाओं का मूल्यांकन)	0.07	0.07	0
जनजातीय कार्य मंत्रालय (उषरमुक्ति और एनजीओ स्क्रीनिंग)	0.63	0.63	0
जनजातीय कार्य मंत्रालय (जीआईए योजनाएं)	0.05	0.05	0
जनजातीय कार्य मंत्रालय (क्षेत्र निरीक्षण)	0.27	0.27	0
जनजातीय कार्य मंत्रालय (क्षेत्र निरीक्षण)	0.27	0.12	0.12
उत्कल एल्युमिना इंडिया लिमिटेड (UANAT)	3.74	2.97	0.43
उत्कल एल्युमिना इंडिया लिमिटेड (वाटरशेड)	1.13	0.91	0.57
भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन	4.05	3.03	0.33
केयरिंग फ्रेंड्स	0.5	0.5	0
थॉटवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	0.25	0.25	0

स्रोत	प्रतिबद्ध/ स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2025 तक प्राप्त (करोड़ रुपये में)	2024–25 में प्राप्त हुआ (करोड़ रुपये में)
सीटीडब्ल्यूडी, तेलंगाना	0.20	0.20	0
वेल्टहंगरहिल्फे (WHH)	6.24	0.33	0.33
ओक फाउंडेशन/स्विस फिलांथ्रॉपी फाउंडेशन	3.78	1.23	1.23
एचडीएफसी परिवर्तन	20.13	0	0
फोर्ड फाउंडेशन	7.72	0	0
कमिंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1.7	0	0
जीआईजेड	1	0.32	0.32
यूएनडीपी	0.62	0.36	0.36
कुल (बी)	**187.81**	**77.70**	**15.97**
सी. ग्रांट पार्टनर्स द्वारा सह–वित्त (बीआरएलएफ परियोजना के लिए भागीदारों की पुस्तकों/बही में व्यय)	238.02	355.50	0
कुल (बी)	**238.02**	**355.50**	**0**
कुल (ए+बी+सी)	**445.79**	**453.16**	**15.97**

भागीदारियाँ (पार्टनरशिप)

हम अपने सभी उदार दानदाताओं, सम्मानित सरकारी भागीदारों और समर्पित भागीदार संगठनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

सरकारी भागीदार			
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDIA	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
	कृषि और किसान अधिकारिता विभाग और बागवानी निदेशालय, ओडिशा सरकार		मिशन शक्ति विभाग, ओडिशा आजीविका मिशन, ओडिशा
	ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार		राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार
Government of Maharashtra	आयुक्त कार्यालय मनरेगा, महाराष्ट्र सरकार		बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), असम सरकार
	आदिवासी विकास विभाग, तेलंगाना सरकार	BTC GOV बि टि सि सरकार	राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ
महाराष्ट्र शासन	महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग		पश्चिम बंगाल सरकार
	झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी		आयुक्तालय, जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना

फंडिग पार्टनर्स	
अर्घ्यम	एक्सिस बैंक फाउंडेशन
केयरिंग फ्रेंड्स	यूरोपीयन यूनियन
फोर्ड फाउंडेशन	जीआईजेड
हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन	ओक फाउंडेशन
भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन	स्विस फिलांथ्रॉपी फाउंडेशन
टाटा ट्रस्ट	थॉटवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
यूएनडीपी	उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड (यूएआईएल)
वीएटेकवैबैग	वेल्टहंगरहिल्फे (WHH)

कार्यान्वयन हो रहे सीएसओ भागीदार		
आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति	ग्रीन फाउंडेशन नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज एन्हांसमेंट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट	समर्थन
अधिकार	हरितिका	समावेश
आगा खाँ रूरल सपोर्ट प्रोग्राम – इंडिया	हर्ष ट्रस्ट	संबलपुर एकीकृत विकास संस्थान
एग्रोक्रैट्स' सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट	आइडियल डेवलपमेंट एजेंसी	समर्थ ट्रस्ट
एजेएसए	भारतीय ग्रामीण सेवाएं	संपर्क
अरुणोदय	जन जागरण केंद्र	संगता
एसोसिएशन फॉर सोशल एडवांसमेंट	जन मुक्ति अनुसंधान	सहभागी
बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन	जनसहज ग्रामीण विकास ट्रस्ट	सेवन सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस
बस्तर सेवक मंडल	जीवन विकास संस्था	सेवा

कार्यान्वयन हो रहे सीएसओ भागीदार		
बोलंगीर ग्रामोद्योग समिति	काबिल	शमिता मठ (एसएम)
CARM–दक्ष	कलामंदिर	श्रमिक शक्ति संघ
सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट	खोज	सृष्टि
सेंटर फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट	क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति	सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट
सेंटर फॉर पीपल'स फॉरेस्ट्री	कृषक सहयोग संस्थान	श्रीजन
सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट	कृषि विकास	सपोर्ट
चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं सोध संस्थान	लोक कल्याण परिषद	सरगुजा ग्रामीण विकास संस्थान
कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू रूरल अवेकनिंग	लोकदृष्टि	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज सेंटर	मानव जीवन विकास समिति	एक्शन नॉर्थईस्ट ट्रस्ट
धरती ग्रामोत्थान एवं सहभागिता ग्रामीण विकास समिति	राष्ट्रीय महिला, बाल एवं युवा विकास संस्थान	पूर्वोत्तर अनुसंधान और सामाजिक कार्य नेटवर्किंग
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी	नवनिर्माण सर्व समाज हितार्थ संस्था नंदुरबार	ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया
ग्राम सुधार समिति लोक शक्ति समिति (एलएसएस)	परहित समाज सेवा संस्था	विकल्प
ग्रामीण सेवा संस्थान	पीपुल्स साइंस इंस्टिट्यूट	विकास संवाद समिति
ग्रामीण समास मुक्ति ट्रस्ट	प्रदान	वाटरशेड ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट
ग्रामीण विकास ट्रस्ट	प्रगति ग्रामीण विकास संस्थान	वॉटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क
ग्रामीण विकास संस्थान	राष्ट्रीय कृषि शिक्षा संस्थान	विकास के लिए युवा परिषद विकल्प
ग्रामीण युवा प्रगतिशील मंडल	ग्रामीण विकास संघ	यूथ रूरल एसोसिएशन
ग्राम्य विकास मंच	सहभागी समाज सेवी संस्थान	विकल्प

शासन व्यवस्थाः पारदर्शिता और जवाबदेही, ऑडिट और संगठनात्मक संरचना

बीआरएलएफ ने नियमों और विनियमों के अनुसार सभी अनिवार्य जीबी और ईसी बैठकें आयोजित की हैं। अपनी स्थापना के बाद से, बीआरएलएफ ने 21 आम सभा की बैठकें और 32 कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित की हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बीआरएलएफ ने दो आम सभा की बैठकें और तीन कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित कीं।

वित्तीय प्रणाली, नियंत्रण, ऑडिट और कार्य पर पारदर्शिता

बीआरएलएफ (BRLF) अपने नियमों और विनियमों (R&R) के अनुसार काम करता है। ये नियम वित्तीय कार्यों के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध में वित्त और ऑडिट समिति (FAC) से आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति और आम सभा (जनरल बॉडी) मिलकर वार्षिक कार्य योजना और बजट अनुमान (BE) को मंजूरी देते हैं। इसी तरह, वित्तीय वर्ष के बीच में, संशोधित अनुमानों (RE) को कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वित्त और लेखा टीम में चार पूर्णकालिक सदस्य और एक वित्तीय परामर्शदाता हैं। यह सारा काम वित्त और ऑडिट समिति की देखरेख और समीक्षा में होता है।

अनुदान प्रबंधन, एमआईएस और मानव संसाधन एवं एडमिन के लिए ऑनलाइन ऐप

वित्तीय अनुदानों का प्रबंधन एमआईएस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसमें बजट तैयार करना, संशोधित बजट, सीएसओ से प्राप्त वित्तीय रिपोर्टें, धनराशि की मांग और अनुदान समझौते की शर्तों के अनुसार धनराशि जारी करना शामिल है। ये सभी उप–प्रक्रियाएँ अनुमोदन प्रणाली के अंतर्गत चलती हैं, जिसमें परियोजना प्रभारी, सीईओ और वित्त विभाग की भूमिका होती है। सीएसओ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तिमाही वित्तीय रिपोर्ट पोर्टल पर ट्रायल बैलेंस, बैंक विवरण और लेखापरीक्षित रिपोर्ट जैसे सहायक दस्तावेज संलग्न करने की सुविधा उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर प्रत्येक परियोजना का वित्तीय डैशबोर्ड उपयोग करके एमआईएस रिपोर्ट निकाली जा सकती है।

ऑडिट

सीएजी ने बीआरएलएफ का दो बार ऑडिट किया है— पहली बार वर्ष 2017 में (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए) तथा दूसरी बार वर्ष 2018 में (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए)। दोनों ही परीक्षणों में कोई प्रणालीगत जोखिम नहीं पाया गया, केवल प्रक्रियागत टिप्पणियाँ दर्ज की गईं ताकि वर्तमान अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बीआरएलएफ ने वित्तीय वर्ष 2024–25 तक सभी वर्षों के ऑडिट किए गए बही खाते समय पर प्रस्तुत किए हैं।

संगठनात्मक संरचना

पेरोल (पूर्णकालिक)	परामर्शदाता (अल्पकालिक)	कुल कर्मचारी
33	27	60

संगठनात्मक संरचना

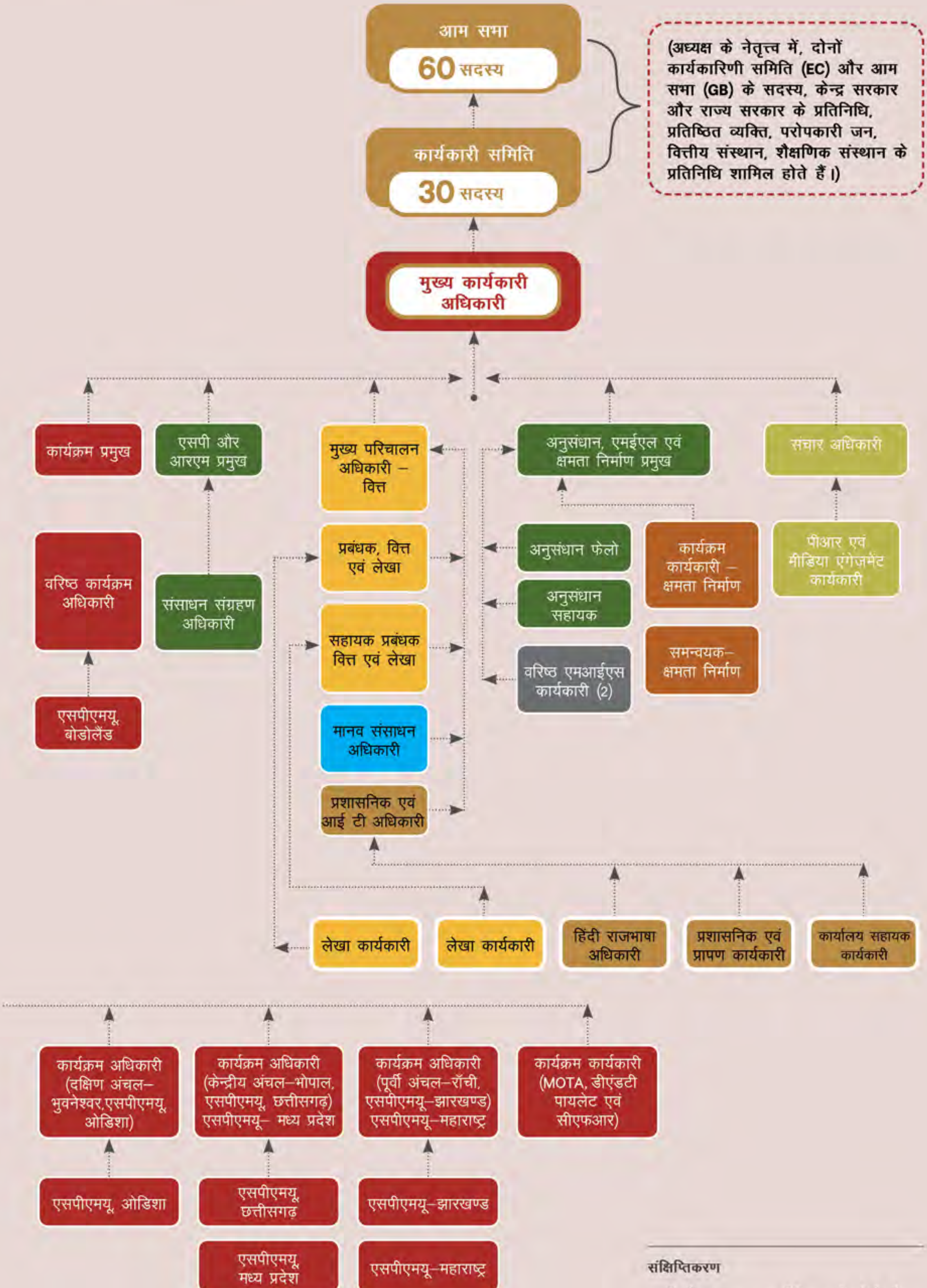

संक्षिप्तिकरण

एसपी और आरएम – रणनीतिक भागीदारियाँ और संसाधन संग्रहण,

एसपीएमयू – राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

वित्त और लेखा

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ऑडिट किए गए खाते (आम सभा / कार्यकारी समिति द्वारा ऑडिट किए गए खातों के अनुसमर्थन के बाद अपडेट किए जाने के लिए)

बीआरएलएफ की कुल आय वित्तीय वर्ष 2024–25 में 36.13 करोड़ रुपये रही, जिसमें 18.83 करोड़ रुपये ब्याज एवं अन्य आय तथा 17.30 करोड़ रुपये दाता अनुदानों से प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कुल व्यय 37.78 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। कार्यक्रम व्यय, जिसमें सीएसओ भागीदारों को दिए गए अनुदान एवं प्रत्यक्ष क्रियान्वयन शामिल हैं, वर्ष के दौरान कुल व्यय का चौथे– पाँचवे हिस्से से अधिक रहा और यह प्रमुख व्यय मद बनी रही। इस वित्तीय वर्ष में आय की तुलना में व्यय 1.65 करोड़ रुपये अधिक रहा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 का बजट अनुमान

इस वर्ष कुल आय (जिसमें निश्चित ब्याज आय और अनुदान शामिल हैं) का अनुमान 57.19 करोड़ रुपये है, जबकि व्यय का अनुमान 64.30 करोड़ रुपये है। इस प्रकार 7.11 करोड़ रुपये की कमी अनुमानित है। संसाधन जुटाने के प्रयासों से लगभग 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है, जिससे इस कमी की आंशिक पूर्ति हो सकेगी। आय से अधिक व्यय की पूर्ति, नये जुटाए गए संसाधनों और पिछले वर्षों से उपलब्ध अधिशेष से की जाएगी।

वैधानिक ऑडिट

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बीआरएलएफ का वैधानिक लेखा परीक्षण एमध्एस ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पूरा किया। इसके बाद वित्त एवं लेखा परीक्षण समिति (थ।ठ) ने रिपोर्ट की समीक्षा की और कार्यकारी समिति तथा सामान्य निकाय ने इसे नियमों के अनुसार मंजूरी दी। एमध्एस ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी तीन वर्ष से यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं और दो वर्ष का विस्तार भी पूरा कर चुके हैं। अब नये वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

आंतरिक / अनुदेयी ऑडिट

आंतरिक लेखा परीक्षक (ऑडिटर) एक वर्ष के लिए चुना जाता है और हर वर्ष या छह महीने के अंतर पर लेखा परीक्षण किया जाता है। बीआरएलएफ हर साल अपने अनुदान भागीदारों का भी ऑडिट कराता है। इसके लिए भागीदारों को अनुदान उपयोग प्रमाणपत्र जमा करना होता है। वर्ष 2024–25 के लिए मैसर्स टी.आर. चड्ढा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आंतरिक लेखा परीक्षक रहे। साथ ही, मैसर्स बंसल एंड कंपनी और मैसर्स संगल एंड एसोसिएट्स भी अनुदेयी ऑडिट का काम पहले की तरह करते रहे। दोनों ही सीएजी की सूची में भी शामिल हैं।

अनुदान ऑडिट केवल परियोजना अनुदानों तक सीमित नहीं रहता। इसमें अनुपालन और सुशासन, बैंकिंग और संचालन, नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन भी शामिल होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में जो टिप्पणियाँ और सुझाव आते हैं, उन्हें हम संबंधित सीएसओ के साथ साझा करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया मिलने के बाद, हम अगली ऑडिट प्रक्रिया में यह देखते हैं कि क्या कार्रवाई हुई।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एमध्एस टी.आर. चड्ढा एंड कंपनी ने आंतरिक ऑडिट पूरा कर लिया। रिपोर्ट में कोई विशेष प्रणालीगत समस्या नहीं आई, किन्तु कुछ प्रक्रियागत सुधार सुझाए गए हैं जिन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

वैधानिक अनुपालन

- बीआरएलएफ का आयकर मूल्यांकन वित्त वर्ष 2023–24 तक पूरा हो गया है और कोई लंबित कार्रवाई/कार्यवाही नहीं है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सभी वार्षिक वैधानिक फाइलिंग, जैसा कि भूमि कानूनों के अनुपालन में आवश्यक है, पूरी हो गई है। सभी नियमित नियामक फाइलिंग भी अपडेटेड हैं। वर्तमान तारीख तक कोई प्रतिकूल/दंडात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है।
- आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत छूट जारी की गई है।
- एफसीआरए पंजीकरण 31 मार्च 2029 तक वैधता के साथ नवीनीकृत किया गया है।

बीआरएलएफ की वित्त एवं ऑडिट समिति (FAC) की बैठकें

बीआरएलएफ की वित्त एवं लेखा परीक्षण समिति की तीन बैठकें क्रमशः 16 अगस्त 2024, 14 नवम्बर 2024 और 24 मार्च 2025 को हुईं। इन बैठकों में वित्त, बजट, संशोधित अनुमान, लेखा परीक्षण और वैधानिक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई।

समिति ने वर्षभर समय–समय पर ऑडिट बही खातों, बजट, संशोधित अनुमानों और कोष (कॉर्पस) के उपयोग पर अपने सुझाव और मार्गदर्शन दिए। बीआरएलएफ ने समिति के सुझावों और दिशा–निर्देशों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की।

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule No	As at 31st March, 2025	As at 31st March, 2024
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	220,153,078	217,887,438
Grant Unspent Balance	C	25,053,480	34,292,320
Fixed Assets Fund	D	2,825,751	2,028,951
Reserve And Surplus	E	169,483,692	186,236,759
Current Liabilities And Provisions	F	29,719,985	12,357,876
Total		**2,447,235,986**	**2,452,803,344**
ASSETS			
Fixed Assets out of Corpus/Endowment Fund	G-I	5,278,152	4,723,962
Fixed Assets-Out of Grants	G-II	2,825,751	2,028,951
Investments of Corpus Fund	H	2,090,560,000	2,090,560,000
Investment of Endowment Fund	I	218,277,835	216,183,835
Current Assets:			
Grant Receivable	C	7,820,016	4,903,074
Cash And Bank Balance	J	50,134,973	58,097,683
Other Current Assets	K	72,339,259	76,305,839
TOTAL		**2,447,235,986**	**2,452,803,344**

Significant Accounting Policies — P

Contingent Liabilities & Notes to Accounts — Q

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 16/09/2025

Girish Yashwant Prabhune
President

Kuldip Singh
Chief Executive Officer

Sushil Pal
Manager- Finance & Accounts

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule No	Current Year 2024-25	Previous Year 2024-25
(A) INCOME			
Grant Income to the extent utilised	C	173,006,322	161,477,394
Other Income	L	188,265,951	191,895,589
TOTAL(A)		**361,272,273**	**353,372,983**
(B) EXPENDITURE			
Grant Expenditure to the Extent Utilised			
Program Expenses incurred through CSOs	} C	127,333,438	117,187,585
Program Expenses incurred by BRLF		38,499,165	34,065,739
Establishment Expenses		6,348,844	7,443,576
Other Administration expenses		125,900	886,660
Fixed Asset Procured		698,975	1,893,834
		173,006,322	**161,477,394**
Expenditure-Ford Endownment	M	10,812,503	8,551,774
Expenditure-Tata Trust Endowment Fund	N	9,364,014	8,468,401
Expenditure from MoRD	O	183,244,899	157,284,613
Depreciation	G-I	1,354,899	1,861,144
TOTAL(B)		**377,782,637**	**337,643,326**
SURPLUS /(DEFICIT) DURING THE YEAR(A-B)		**(16,510,364)**	**15,729,657**

Significant Accounting Policies	P
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Anil Kumar Aggarwal	**Girish Yashwant Prabhune**	**Kuldip Singh**	**Sushil Pal**
Partner	**President**	**Chief Executive Officer**	**Manager-Finance & Accounts**

M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 16/09/2025

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

(Amount in Rs.)

Receipts	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24	Payments	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
Opening Balance as on 1.4.2024			**Payments during the year:**		
Bank Balances in Saving Accounts	58,097,683	66,715,033	**Grants Refunded (a)**		
Fixed Deposits with Banks	2,306,743,835	2,304,432,835	-MoTA Research & Screening	-	247,284
	2,364,841,518	**2,371,147,868**		-	**247,284**
Receipts during the year:			**Expenditure/ Payments (b)**		
Grants from Local Sources(a):			Disbursement To Project Partners (net of Refund)	227,983,652	230,971,388
Axis Bank Foundation CG - Phase 2	40,587,126	70,850,654	Payments For Program Expense	64,719,774	57,968,816
Axis Bank Foundation CG - Phase 3	43,300,000	-	Establishment Expense	14,256,745	9,376,532
Axis Bank Foundation - Maharashtra	36,905,920	34,800,000	Other Administrative Expense	10,045,137	11,414,682
SBI Foundation	3,333,979	10,966,637	Ford Endowment Fund Expenses	10,942,113	8,535,303
MOTA	1,175,875	-	Tata Trust Endowment Fund Expenses	9,364,014	8,468,401
UAIL-UNAT	4,307,029	12,192,903		**337,311,436**	**326,735,122**
UAIL-Watershed	5,682,405	3,409,443			
Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahanabdak Naryadit	2,000,000	3,607,843	**Fixed Assets Purchased out of(c)**		
Tribal Welfare Department (Telangana)	-	2,000,000	-Capital Advance (WIP)	1,870,500	575,250
Thoughtworks Technologies (India) Pvt.	-	2,500,000	- Fixed assets out of MoRD	758,591	2,350,161
Grant for NCNF Project MP	-	5,000,000	- Fixed assets out of Grant Fund	698,974	1,893,834
UNDP	3,692,535	-		**3,328,065**	**4,819,245**
	140,984,869	**145,327,480**			
Grants in Foreign Sources(b):			**Other Payments (d)**		
- GIZ (MP-Project)	3,158,542	-	TDS deducted & Deposited	11,061,884	9,328,964
- WHH (OD-Project)	3,321,479	-	Employees Providend fund	5,701,507	4,561,747
- Oak Foundation (WB-Project)	12,287,000	-	Bank Charges	201	3,422
	18,767,021	-	Security Deposits	55,000	103,000
			Amount receivables/TDS	-	243,688
Interest Income (c)				**16,818,592**	**14,240,821**
Interest on Fixed Deposit with Banks-Net TDS	131,272,592	136,219,484			
Interest accrued on Fixed Deposits received in current year	46,742,356	45,551,705	**Total Payments during the year(a to d):**	**357,458,092**	**346,042,472**
Interest on Saving Bank Account	5,580,437	5,056,561			
Interest on Tata Fund- Saving Bank	281,403	328,307			
Interest on Tata Fund- Fixed Despoit	6,949,267	6,811,585	**Closing Balance as on 31.3.2025**		
Interest on Income Tax Refund	20,093	-	Bank Balances in Saving Accounts	50,134,973	58,097,683
	190,846,148	**193,967,642**	Fixed Deposits with Banks	2,308,837,835	2,306,743,835
				2,358,972,808	**2,364,841,518**
Other Receipts (d)					
Miscellaneous Receipts	27,476	-			
Donation for Stipend MA-RM	179,001	410,000			
Sponsorship fees for Webinar	-	31,000			
Income Tax Refund	389,766	-			
Advance Interest(TDS)	395,102				
	991,345	**441,000**			
Total Receipts during the year(a+b+c+d):	**351,589,383**	**339,736,122**			
	-				
TOTAL	**2,716,430,901**	**2,710,883,990**	**TOTAL**	2,716,430,901	2,710,883,990

As per our report of even dated attached

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN : 000038N

Anil Kumar Aggarwal
Partner
M. No. 087424
Place: New Delhi
Date: 16/09/2025

T.V.A. & CO. New Delhi Chartered Accountants

Girish Yashwant Prabhune
President

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Kuldip Singh
Chief Executive Officer

Sushil Pal
Manager- Finance & Accounts

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

SCHEDULE A - Corpus Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2025		As at 31st March 2024
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund

(i) Ford Foundation Endowment fund (FCRA Funds)				
Opening Balance		105,438,112		104,533,649
Add: Transfer from saving bank interest (Schedule L)	71,766		64,908	
Add: Transfer from interest earned on fixed deposits (Schedule L)	839,968	911,734	839,555	904,463
Closing balance of Ford Foundation Endowment Fund		106,349,846		105,438,112
(Refer note No 3 of Schedule R)				
(ii) Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance as on 01-04-2024		112,449,325		111,259,256.16
Add: Transfer from saving bank interest (Schedule L)	42,210		49,246	
Add: Transfer from interest earned on fixed deposits (Schedule L)	1,311,697	1,353,907	1,140,823	1,190,069
Closing Balance of Tata Trust Endowment Fund		**113,803,232**		**112,449,325**
Grand Total (i+ii)		**220,153,078**		**217,887,438**

Note: 15% of the annual interest income received on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. During the financial year, Rs.87,44,645/- is interest income received on FD's & Rs.2,81,403 is interest on saving, totalling Rs.90,26,048/. Total expenditure incurred toward the fund was Rs.93,64,014/- which is more than the interst income. Therefore, An amount of Rs.13,53,907/-(Previous Year Rs.11,90,069) has to be deposited in FDR.

T.V.A. & CO. Chartered Accountants Delhi

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Bharat Rural Livelihoods Foundation
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULE C- Earmarked Grants/Donations Receipts, Utilized during the year and balances as on 31st March, 2025

PARTICULARS	App-I	Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 01.04.2024	RECEIPT DURING THE YEAR form Donor: Grant Receipt/ (net of Refund)	RECEIPT DURING THE YEAR form Donor: Interest Allocation	Amount Available for Utilisation	EXPENDITURE DURING THE YEAR From Respective Grant: Programme Cost: Incurred through CSO Partner	Programme Cost: Incurred by BRLF	Establishment Cost	Admin Cost	Non-Recurring	Expenses borne by BRLF	Total	Un-Spent Balances/ (Receivables) as on 31.03.2025
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9+10	12=4-11
(A) Local Grants													
UAIL-UANAT	1	2,051,298	4,307,029	171,125	6,529,452	5,547,455						5,547,455	981,997
UAIL-Watershed	2	2,591,554	5,682,405	38,323	8,312,282		10,166,479					10,166,479	(1,854,197)
Thought Works	3	1,612,486	-	30,176	1,642,662	1,642,662	-	-				1,642,662	-
SBI Foundation- Watershed (JH) Project	4	4,251,261	3,333,979	117,779	7,703,019	6,981,318	1,057,615	429,912	5,900			8,474,745	(771,726)
MH TDD +HDI Project (Shabari)		(2,242,703)	2,000,000	-	(242,703)	-	-	-	-		(242,703)	(242,703)	-
Axix Bank Foundation - Phase-II (CG)	5	191,038	40,587,126	18,363	40,796,527	38,848,708	1,184,823	762,996				40,796,527	-
Axix Bank Foundation - Phase-III (CG)	6	-	43,300,000	85,803	43,385,803	35,541,307	3,353,917	989,289				39,884,513	3,501,290
Axix Bank Foundation - MH	7	12,931,703	36,905,920	67,288	49,904,911	37,833,748	11,430,828	2,691,544				51,956,120	(2,051,209)
CTWD, Telangana	8	1,617,156	-	-	1,617,156	938,240	205,018					1,143,258	473,898
UNDP		-	3,692,535	-	3,692,535	-	-	-	-	-		-	3,692,535
Sub Total (I)		**23,003,793**	**139,808,994**	**528,857**	**163,341,644**	**127,333,438**	**27,398,680**	**4,873,741**	**5,900**	**-**	**(242,703)**	**159,369,056**	**3,972,588**
Government Grants		-											
MoTA- Screening of Porposals	9	(2,660,371)	1,175,875	-	(1,484,496)		422,003	350,000				772,003	(2,256,499)
MoTA- Inspection of NGOs (Meghalaya & Manipur)	10	-	-	-	-		614,875	271,510				886,385	(886,385)
Sub Total (II)		**(2,660,371)**	**1,175,875**	**-**	**(1,484,496)**	**-**	**1,036,878**	**621,510**	**-**		**-**	**1,658,388**	**(3,142,884)**
Total (A)		**20,343,422**	**140,984,869**	**528,857**	**161,857,146**	**127,333,438**	**28,435,558**	**5,495,281**	**5,900**	**-**	**(242,703)**	**161,027,444**	**829,704**
Grant Unspent Balance		**25,246,496**											**8,649,720**
Grant Receivable		**(4,903,074)**											**(7,820,016)**
Previous Year (A) (2023-24)		**8,928,037**	**146,080,196**	**852,822**	**154,861,056**	**117,187,585**	**8,508,758**	**7,443,576**	**3,566**	**1,345,048**		**134,517,633**	**20,343,422**
FOREIGN EARMARKED FUNDS/ DONATIONS (B)													
Hindustan Unilever Foundation	11	9,045,824		214,355	9,260,179		9,260,179	-	-	-		9,260,179	-
GIZ	12	-	3,158,542	50,418	3,208,960		145,287	50,868	120,000	190,440		506,595	2,702,365
Oak Foundation		-	12,287,000	-	12,287,000		-	-	-	-		-	12,287,000
WHH	13	-	3,321,479	62,317	3,383,796		658,141	802,725	-	508,535		1,969,401	1,414,395
Total(B)		**9,045,824**	**18,767,021**	**327,090**	**28,139,936**	**-**	**10,063,607**	**853,593**	**120,000**	**698,975**	**-**	**11,736,175**	**16,403,760**
Previous Figure(B) (2023-24)		**34,344,809**	**-**	**1,660,776**	**36,005,585**		**25,559,981**	**-**	**850,994**	**548,786**	**26,959,761**	**-**	**9,045,824**
Grand Total (A+B)		**29,389,246**	**159,751,890**	**855,947**	**189,997,083**	**127,333,438**	**38,499,165**	**6,348,844**	**125,900**	**698,975**	**(242,703)**	**172,763,619**	**17,233,464**
Grant Unspent Balance		**34,292,320**											**25,053,480**
Grant Receivable		**(4,903,074)**											**(7,820,016)**
Previous Year (A+B) (2023-24)		**43,272,846**	**145,080,196**	**2,513,598**	**190,866,640**	**117,187,585**	**34,065,739**	**7,443,576**	**886,660**	**1,893,834**	**-**	**16,147,794**	**29,389,246**
Grant Unspent Balance		**47062016**											**34,292,320**
Grant Receivable		**(27,068,452)**											**(4,903,074)**

T.V.A. & CO. Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeli Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

Appendix 1 to Schedule C

S.No.		11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Particulars		HUF (JH)	GIZ (MP)	WHH (OD)	UAIL (UANAT)	UAIL (Watershed)	Thoughtworks	SBI Foundation	Axis Bank F-Ph-2 (CG)	Axis Bank F-Ph-3 (CG)	Axis Bank F (MH)	CTWD, Telangana	MoTA-Screening of Porposals	MOTA (Inspection of NGOs Meghalaya & Manipur)	Grand Total
(A) Establishment Expenses															
Staff Salaries		-	-	-	-	-	-	429,912	762,996	989,289	2,644,656		350,000	271,510	5,448,363
EL Provision					-						46,888				
Total (A)		-	-	-	-	-	-	429,912	762,996	989,289	2,691,544	-	350,000	271,510	5,495,251
(B) Program Expenses															
Human Resource/Consultancy cost		962,500	50,868	802,725	-	-									1,816,093
Implementation Cost		7,618,874	131,786	355,131	-	10,166,479	-	1,057,615	1,184,823	3,353,917	11,430,828	205,018			35,504,471
Grant Support to CSOs		-	-		5,547,455		1,642,662	6,981,318	38,848,708	35,541,307	37,833,748	938,240			127,333,438
Trave Expenses		541,320	8,952	156,699		-		-	-		-	-	422,003	614,875	1,743,849
Equipment & supplies						-									-
Capacity Building									-	-	-				-
Local Office Expenses		137,485	4,549	146,311					-						288,345
		9,260,179	196,155	1,460,866	5,547,455	10,166,479	1,642,662	8,038,933	40,033,531	38,895,224	49,264,576	1,143,258	422,003	614,875	166,686,196
Expense Borne by BRLF						-	-			-					-
Total (B)		9,260,179	196,155	1,460,866	5,547,455	10,166,479	1,642,662	8,038,933	40,033,531	38,895,224	49,264,576	1,143,258	422,003	614,875	166,686,196
(C) Non Recurring Expenditure		-	190,440	508,535		-					-				698,975
Total (C)		-	190,440	508,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,975
(D) Other Admin Expenses															
Office Maintenance Expenses		-	-		-			-							-
Bank Charges		-	-		-	-		-							-
Interest on TDS					-	-									-
Human Resource Cost		-	120,000		-	-									120,000
Water & Electricity-Utilities Expenses															-
Audit Fee						-		5,900	-	-	-	-			5,900
Total (D)		-	120,000	-	-	-	-	5,900	-	-	-	-	-	-	125,900
Grand Total (A+B+C+D)		9,260,179	506,595	1,969,401	5,547,455	10,166,479	1,642,662	8,474,745	40,796,527	39,884,513	51,956,120	1,143,258	772,003	886,385	173,006,322

T.V.A. & CO. Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeli Bagh New Delhi 110049

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

SCHEDULE D -Fixed Assets Fund

(Amount Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2025		As at 31st March 2024
Opening Balance		2,028,951		180,184
Addition during the year		1,418,979		
Less: Deletion/adjustment during the year		21,230		
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased		600,949		20,773
Total		2,825,751		2,028,951

SCHEDULE E - Reserve And Surplus

Surplus				
Opening Balance		186,236,759		170,507,101
Less: Receivable Adjustment due to non recoverable from Donor (Refer Note No 6 of Schedule R)		342,703		
Net Balance		185,894,056		170,507,100
Add: Surplus/(Deficit) transferred from Statement of Income over Expenditure for the year		(16,510,364)		15,729,659
Closing Balance		169,483,692		186,236,759

SCHEDULE F - Current Liabilities And Provisions

Amount Payable to CSO Partners		18,211,108		1,045,406
TDS Payable		329,109		1,397,138
Sundry Creditors		2,188,060		3,363,104
PF Payable		-		453,157
PT Payable		833		1,554
Expenses Payable		1,380,244		493,997
Advances		1,128		32,711
Excess interest credited by Bank(FDs)		395,169		
Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	2,919,543		2,718,810	
- Gratuity	3,328,156	7,247,699	3,392,097	6,110,907
Total		29,719,985		12,357,876

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

Schedule G-I-Fixed Assets out of Corpus/Endowment Fund

(Amount in Rs)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2024	Addition		Deduction/ Transfer	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2025
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	1,625,899	158,168	16,999	-	1,801,166	717,067	1,084,099
Office Equipment	15%	481,023	281,271	117,275	-	879,568	123,125	756,343
Furniture & Fixture	10%	790,010	184,878	-	-	974,888	97,489	877,399
Sub Total		2,896,933	624,317	134,274	-	3,655,522	937,681	2,717,841
INTANGIBLE								
Computer Software	33.33%	1,251,779	-	-	-	1,251,779	417,218	834,561
MIS Software(WIP)		575,250	1,150,500			1,725,750	-	1,725,750
Sub Total		1,827,029	1,150,500	-	-	2,977,529	417,218	2,560,311
Total		4,723,962	1,774,817	134,274	-	6,633,051	1,354,899	5,278,152
PREVIOUS YEAR		4,420,345	2,791,276	660,650		6,009,856	1,863,144	4,723,962

Schedule G-II-Fixed Assets- Out of Grant

(Amount in Rs)

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2024	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2025
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
TANGIBLE								
Computer Hardware	40%	876,481	-	408,372	21,230	1,263,623	521,307	841,916
Office Equipment	15%	710,468		135,230		845,698	116,712	728,986
Furniture & Fixtures	10%	442,007	-	155,372	-	597,379	52,970	545,409
Sub Total		2,028,951	-	698,974	21,230	2,706,700	500,949	2,105,751
INTANGIBLE								
MIS Software (WIP)		-	720,000		-	720,000	-	720,000
Sub Total		-	720,000	-	-	720,000	-	720,000
Total		2,028,951	720,000	698,974	21,230	3,426,700	600,949	2,825,751
PREVIOUS YEAR		494,229	45,310	1,848,528	-	2,388,566	359,666	2,028,951

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

SCHEDULE L - Other Income

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2024-25		Previous Year 2023-24
Saving Bank Interest	5,861,840		5,384,868	
Less:				
- Allocated to FCRA Grant Fund	327,090		1,660,776	
- Allocated to Local Grant Fund	528,857		852,822	
- 10% reinvested to Ford Foundation Endowment Fund	71,766		64,908	
- 15% Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	42,210	4,891,917	49,246	2,757,116
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	167,295,083		172,788,429	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,786,000		8,747,744	
- Ford Foundation Endowment Fund	8,286,155		8,335,285	
- Axis Bank Foundation	-		86,300	
Total	184,367,238		189,957,758	
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	839,968		839,555	
Less: 15% Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	1,311,697	182,215,573	1,140,823	187,977,379
Interest earned by the Grant Partners- CSOs		931,891		720,090
Donation for Stipend MA-RM		179,001		410,000
Interest on Income Tax Refund		20,093		-
Income from Workshops		-		31,000
Miscellaneous Income		27,476		3
Total		**188,265,951**		**191,895,589**

SCHEDULE M - Expenses incurred from FORD Endowment

Program Expenses				
Jharkhand SPMU Expenses	2,165,977			
Staff Salaries	7,236,016		6,063,396	
Employer Contribution to Provident Fund	-		727,608	
Earned Leave expenses	-	9,401,993	45,029	6,836,033
Other Administration Cost				
Satff salary	1,410,368		1,669,969	
Earned Leave expenses	-		17,624	
IT and Online Subscription Exp	-		28,103	
Bank charges	142	1,410,510	45	1,715,741
Total		**10,812,503**		**8,551,774**

SCHEDULE N - Expenses from Tata Trust Endowment Fund

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2024-25		Previous Year 2023-24
Tata Trust Establishment Cost				
Staff Salaries		9,260,706		8,323,197
Earned Leave Expenses		103,308		145,204
Total		**9,364,014**		**8,468,401**

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

SCHEDULE O - Expenses from MORD

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		Current Year 2024-25		Previous Year 2023-24
MoRD Program Cost				
Grant support to CSOs				
CFP 2	-		1,386,942	
West Bengal Mega Watershed Project	-		14,064,031	
Odisha APC Project Ph-1	-		48,298,091	
Odisha APC Project Ph-2	59,441,942		**13,061,519**	
Odisha UANAT Project (UAIL)	526,204		299,354	
Madhya Pradesh NCNF Project	-		4,754,696	
Jharkhand Mega Watershed Project	6,808,786		1,301,359	
Maharashtra Mega Watershed Project	6,753,391		2,587,126	
MH (TDD+HDI) Livelihood Project	-		1,977,947	
Telangana CFR Project	3,593,298	77,123,621	2,102,288	89,833,353
Capacity Building Expenses	1,239,726		2,459,886	
Capacity Building support through CSOs	**43,689,334**		11,818,406	
Implementation exp for APC Project for Odisha Ph-2	906,006		1,780,268	
Implementation exp for NCNF Project for MP	2,019,960		2,113,890	
Implementation exp for Megawatershed Project for CG Ph 2	67,909		197,379	
Implementation exp for Megawatershed Project for JH	2,567,800		1,215,110	
Implementation exp for Livelihood Project for MH (TDD+HDI)	-		801,748	
Implementation exp for CFR Project for Telangana	614,616		552,568	
Implementation exp for Megawatershed Project for MH	540,000		38,571	
Implementation exp of UAIL watershed Project	446,300		-	
Event, Meetings and Workshop Expenses	3,883,719		815,578	
Travel Expenses	1,019,622		1,387,851	
DNT Project Expenses	316,753		806,093	
DNT support through CSO	**1,471,358**		2,638,669	
Online MIS software & Website Expenditure	1,369,469		780,646	
Research Expenses	2,375,571		588,528	
Resource Mobilization expesnes	470,480		201,186	
Communication, PR, Media & Social Media Management etc	1,873,091		2,674,633	
Bodoland Project Expenses	6,474,127	71,345,841	5,035,657	35,906,667
MoRD Establishment Cost				
Staff Salaries	22,081,181		12,147,915	
Employer Contribution to Provident Fund	-		1,457,750	
Earned Leave expenses (**refer Note No 8 of Schedule -Q)**	896,761		2,347,173	
Gratuity Expenses (**refer Note No 8 of Schedule -Q)**	870,831		835,309	
Recruitment expenses	163,029		4,061,751	
EPF Admin Charges	132,078		115,512	
Staff welfare expenses	192,494		159,081	
Relocation expenses	181,221		127,414	
Medical & Accidental Insurance Expenses	471,701		310,124	
Consultancy Fees for PF calculation	46,728	25,036,024	42,480	21,604,509
MoRD Other Administration Cost				
Office Rent	3,392,500		2,967,000	
Meetings/Events	2,987,715		2,417,713	
Tally/FactoHR/ Computax	344,878		55,293	
Audit Fees	253,847		210,925	
Communication Expenses	751,709		755,200	
Stationary expenses	281,167		464,608	
Water & Electricity expenses	336,576		302,331	
Office Maintenance Expenses	523,505		441,266	
Equipment Maintenance Expenses	97,320		119,594	
Postage & courier	50,857		41,095	
Miscellaneous Expenses	6,469		19,530	
Hindi Language Promotion	34,163		66,701	
Consultancy/Internship/Professional Fee	670,660		2,060,174	
Insurance of Fixed assets	8,047	9,739,413	18,654	9,940,084
Total		**183,244,899**		**157,284,613**

T.R.A. & CO. Chartered Accountants New Delhi

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049 BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

BRLF
BHARAT RURAL
LIVELIHOODS FOUNDATION

Bharat Rural Livelihoods Foundation
C-32, 2nd Floor, Neeti Bagh, New Delhi - 110049
Telephone: +91 11 4606 1935
E-Mail: info@brlf.in